हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

22 जनवरी, 1998

(प्रथम बैठक)

खण्ड-1, अंक-3

अधिकृत विवरण

विषय सूची

वीरवार, 22 जनवरी, 1998

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	3(1)
वाक-आउट	3(10)
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)	3(11)
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	3(14)
सचिव द्वारा घोषणा	3(18)
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना का उत्तर देने के लिए समय बढ़ाना	3(18)
सरकार द्वारा निर्वाचन आयोग के निर्देशों की अभिकथित उल्लंघना संबंधी मामला उठाना	3(18)
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना	3(19)
बैठक का स्थगन	3(20)
सदस्य का नाम लेना	3(21)
वाक-आउट	3(22)
डॉ० वीरेन्द्र पाल अहलावत के नेमिंग को रद्द करना	3(23)
सदस्य का नाम लेना	3(23)
वाक-आउट	3(24)
राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)	3(24)
हरियाणा लोक दल (राष्ट्रीय) पार्टी के सदस्यों द्वारा सदन की कार्यवाही में भाग न लेना	3(25)
राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)	3(2[illegible])

मूल्य : [illegible]

बैठक का स्थगन	3(36)
राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)	3(36)
बैठक का समय बढ़ाना	3(40)
राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)	3(41)
बैठक का समय बढ़ाना	3(43)
राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)	3(43)
राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान	3(44)
वर्ष 1997-98 के अनुपूरक अनुमानों पर चर्चा तथा मतदान	3(44)
(i) राज्य के राजस्वों पर प्रभारित व्यय के अनुमानों पर चर्चा	3(44)
(ii) अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान	3(44)
अप्रैल से जुलाई, 1998 के लेखानुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान	3(49)
समितियों की रिपोर्टस पेश करना	3(54)
(i) पब्लिक अकांउटस कमेटी की 45वीं रिपोर्ट	3(54)
(ii) सबोर्डिनेट लैजिस्लेशन कमेटी की 29वीं रिपोर्ट	3(55)
बिल्स-	3(55)
(i) दि हरियाणा नौन-बायोडिग्रेडेबल गारबेज (कंट्रोल) बिल, 1998.	3(55)
बैठक का समय बढ़ाना	3(57)
(i) दि हरियाणा नौन-बायोडिग्रेडेबल गारबेज (कंट्रोल) बिल, 1998 (पुनरारम्भ)	3(58)
(ii) दि हरियाणा एफिलिएटिड कालेजिज (डिक्योरिटी आफ सर्विस) अमैंडमैंट बिल, 1998	3(58)

हरियाणा विधान सभा

वीरवार, 22 जनवरी, 1998 (प्रथम बैठक)

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में प्रातः 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (प्रो० छतर सिंह चौहान) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष : मैम्बर साहेबान, अब सवाल होंगे।

तारांकित प्रश्न संख्या 466

यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य, श्री देवराज दीवान सदन में उपस्थित नहीं थे।

तारांकित प्रश्न संख्या 487

यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य कैप्टन अजय सिंह यादव सदन में उपस्थित नहीं थे।

Evasion of Tax

***495. Shri Krishan Lal :** Will the Minister for Commercial Taxes be pleased to state the number of cases of tax evasion detected by the Vigilance Department in the State during the year 1996-97; togetherwith the number of officers/officials involved therein alongwith the details of the action taken against them ?

नगर एवं शहरी आयोजना मंत्री (सेठ सिरी किशन दास) : विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

वर्ष 1996-97 के दौरान राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा ने टैक्स की चोरी के एक केस का पता लगाया है। कर निर्धारण अधिकारियों के विरुद्ध एक 1,40,200 रुपये का अग्राह्य रिफण्ड डि-आयल्ड राईस ब्रान केक के व्यवहारी को देने का आरोप था। दो कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा किए गए रिफण्ड के आदेश हरियाणा विक्रय कर अधिकरण के निर्णय पर आधारित थे। रिफण्ड के एक आदेश की रवीजनल अथार्टी द्वारा भी पुष्टि की गई है। रिफण्ड की स्वीकृति देते समय कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा यह माना गया कि व्यवहारी द्वारा राशि बिना वसूल किए जमा कराई गई। तथापि, राज्य चौकसी ब्यूरो को इसके विपरीत कुछ दस्तावेजिक प्रमाण उपलब्ध हुए हैं, और वाणिज्य कर विभाग द्वारा आगे मामले की छानबीन की जा रही है।

उपरोक्त के अतिरिक्त, राज्य चौकसी ब्यूरो से पंचकूला के ठेकेदारों द्वारा टैक्स की चोरी के सम्बन्ध में एक स्त्रोत रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। मामले के निरीक्षण से यह मालूम हुआ है कि टैक्स की देय राशि ठेकेदारों से वसूल की जा रही है।

श्री कृष्ण लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जिनके विरुद्ध कार्यवाही की गई उनका पूरा ब्यौरा क्या है ?

सेठ सिरी किशन दास : स्पीकर साहब, वर्ष 1996-97 में चौकसी विभाग द्वारा कर की चोरी के दो मामले बताए गए जिनमें से एक मैसर्ज़ श्याम सोलवैंट करनाल का है जो तेल निकाली खल का व्यापार करता है। इसके 1992-93 और 1993-94 के केसिज़ सेल्ज़ टैक्स अधिकारियों ने 1994 तथा 1996 में निपटाए थे। वर्ष 1994 में ट्रिब्यूनल ने इस आईटम को कर से माफ माना था जिसके कारण अधिकारियों ने इस फर्म को 1 लाख 40 हजार 200 रुपए का रिफण्ड दे दिया तथा उन्होंने यह भी माना कि फर्म ने यह टैक्स अपनी जेब से दिया था। अब 1997 में चौकसी विभाग के नोटिस में एक बिल की कापी आई है जिसमें इस फर्म द्वारा 200 रुपए के लगभग का टैक्स वसूल किया हुआ है। चौकसी विभाग ने इस सम्बन्ध में आगामी कार्यवाही के लिए केस भेजा है। मामले में आगामी कार्यवाही के लिए जांच डी०ई०टी०सी० करनाल को दे रखी है। फर्म से रिकार्ड प्राप्त किया जा रहा है। जांच के बाद फर्म और दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। यदि फर्म दोषी पाई गई तो उससे पैनल्टी जो दुगनी है, ली जाएगी।

Damage caused to Paddy due to 'Nartor' disease

***521. Shri Ramesh Kumar :** Will the Minister for Revenue be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to provide compensation to the farmers of Baroda constituency whose paddy crops has been badly damaged due to (Nartor) disease and recent rainfall ?

राजस्व मंत्री (श्री सूरजपाल सिंह) : बड़ौदा निर्वाचन क्षेत्र में "नाड़तोड़" बीमारी तथा वर्षा से धान की फसल को नाममात्र नुकसान होने बारे रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिसका नार्म के मुताबिक कोई मुआवजा देय नहीं बनता।

श्री रमेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि अधिक वर्षा होने के कारण धान का फसल को जो नुकसान हुआ है क्या उसकी रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हुई है, अगर हुई है तो क्या उसके मुताबिक किसानों को मुआवजा दिया जाएगा ? अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब तक जितनी भी सरकारें आई हैं, चाहे वह देवी लाल की सरकार रही हो या कांग्रेस की सरकार रही हो सभी ने ऐसे हालात में किसानों की मदद की है। प्रकृति से जो ओलावृष्टि हुई है या ज्यादा बरसात हुई है उसके कारण जिन किसानों की फसलों की बर्बादी हुई है चाहे धान की फसल की हुई हो या गेहूं की फसल की हुई हो, उन सभी सरकारों की तरफ से उन किसानों को मुआवजा मिला है।

श्री अध्यक्ष : कृपया आप सवाल पूछें।

श्री रमेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री जी बताएंगे कि जो अब किसानों की फसल का नुकसान हुआ है क्या उनको मुआवजा दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, अगर दिया जाएगा तो प्रति एकड़ के हिसाब से कितना दिया जाएगा ?

श्री सूरजपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि फसलों के नुकसान के लिए मुआवजा देने के जो नार्म्ज हैं, उनके अनुसार इस सरकार ने भी किसानों को मुआवजा दिया है। ओलावृष्टि के कारण फसलों का जो नुकसान हुआ है उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं कि इस वर्ष दो बार ओलावृष्टि हुई है। एक बार मार्च-अप्रैल के महीने में और दूसरी बार दिसम्बर के लास्ट में हुई है उसके लिए 3 करोड़ 42 लाख रुपये मुआवजे के किसानों को वितरित किए गए हैं।

तारांकित प्रश्न संख्या 505

यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य,. श्री कैलाश चन्द्र शर्मा सदन में उपस्थित नहीं थे।

Up-gradation of General Hospital, Gurgaon

***500. Shri Dharam Bir Gauba :** Will the Minister for Health be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade General Hospital, Gurgaon ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश महाजन) : जी नहीं।

श्री धर्मबीर गाबा : स्पीकर साहब, यह कहना बड़ आसान है कि "नो सर" ! मैं आपके माध्यम से मंत्री से जानना चाहता हूं कि सिविल होस्पीटल गुड़गांव का दर्जा बढ़ाने में क्या अड़चन है? क्या उसका दर्जा कोई राजनैतिक भेदभाव के कारण नहीं बढ़ाया जा रहा है। गुड़गांव डिस्ट्रक्ट हैड क्वार्टर है, एक इंडस्ट्रीयल टाउन है और वह नैशनल हाई-वे पर है तो फिर उस सिविल होस्पीटल का दर्जा बढ़ाने में इनको क्या दिक्कत है ? गुड़गांव में जितने भी एमरजैंसी केस होते हैं वे सारे दिल्ली को रैफर कर दिए जाते हैं।

श्री ओम प्रकाश महाजन : अध्यक्ष महोदय, उस होस्पीटल में 120 बैड हैं और वहां पर बैड भरने की जो स्थिति है वह 70 परसैंट है और 30 परसैंट बैड खाली रहते हैं तो फिर 120 से ज्यादा बैड बढ़ा दिए जाते हैं तो वे सारे खाली पड़े रहेंगे उसका क्या फायदा है। इसके अलावा उस होस्पीटल की जमीन भी कम है। हुड्डा ने एक प्रोविजन कर रखा है अगर 5 या 7 साल के बाद भविष्य में वहां पर बैड बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी तो वहां पर नया होस्पीटल बना दिया जाएगा। इस समय तो उस होस्पीटल में 120 बैड ही आकूपाई नहीं होते हैं।

श्री धर्मबीर गाबा : उस होस्पीटल के बैड खाली इसलिए रहते हैं क्योंकि वहां पर मरीजों के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। वहां के सारे केसिज़ दिल्ली को रैफर कर दिए जाते हैं। यदि केस दिल्ली को रैफर कर दिए जाते हैं तो फिर उसके बैड कैसे भर सकते हैं। यदि आप उस होस्पीटल को अपग्रेड नहीं करते हैं और उसमें स्पेलिस्ट नहीं भेजते हैं तो बैड्ज की आकूपैंसी कैसी पूरी होगी।

श्री ओम प्रकाश महाजन : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य मंत्री रहे हैं इनको सारी स्थिति का पता है। कल एक सवाल हमारे माननीय सदस्य श्री मनी राम जी ने किया था कि आपने कॅंट्रैक्ट बेस पर डाक्टर क्यों रख लिए। वह इसलिए रख लिए क्योंकि हमारी सरकार को यह चिन्ता है कि जो पी०एच०सीज़०, सी०एच०सीज़० हैं उनके अन्दर उनको नियुक्त किया जाए एच०पी०एस०सी० से अभी तक सिलैक्ट हो कर हमारे पास डॉक्टर नहीं आए हैं। इसलिए हमने कॅंट्रैक्ट बेस पर रख लिए। हमारी पूरी कोशिश है कि हर हॉस्पीटल, हर पी०एच०सी० और हर सी०एच०सी० में डाक्टर पूरे हों। एक बात मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि डॉक्टर्ज़ की जो कमी है यह हमारे से पहले की जो सरकारें 10 या 12 साल रही हैं उनके कारण रही है।

श्री अध्यक्ष : स्वास्थ्य मंत्री, पिछले दिनों कुछ डॉक्टर्ज़ को परमोट करके एस०एम०ओ० बनाया गया था लेकिन उन्होंने आज तक ज्वायन नहीं किया है। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि क्या जब तक नए डॉक्टर्ज़ नहीं आ जाते तब तक उन एस०एम०ओज़० को उनकी पोस्ट पर ज्वायन नहीं कराया जाएगा। नए डॉक्टर्ज़ की यह तो मर्जी है कि वे ज्वायन करें या न करें लेकिन जो डॉक्टर आलरेडी सर्विस में हैं उनको एस०एम०ओ० परमोट कर दिया लेकिन उनको अभी तक एस०एम०ओ० की पोस्ट पर ज्वायन नहीं कराया है। इसका क्या कारण है।

श्री ओम प्रकाश महाजन : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस समय यह इन्फर्मेशन मेरे पास अवेलेबल नहीं है। इस बारे में मैं आपको बाद में बता दूंगा।

श्री धर्मवीर गाबा : स्पीकर साहब, मैं इनसे जानना चाहता हूं कि क्या गुड़गांव सिविल हॉस्पीटल में सभी बीमारियों के स्पैशलिस्ट हैं।

श्री ओम प्रकाश महाजन : वहां पर सभी तरह का स्टाफ मौजूद है।

श्री धर्मवीर गाबा : मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या गुड़गांव में पी०एम०ओ० है ?

श्री ओम प्रकाश महाजन : वहां पर पी०एम०ओ० नहीं है। पी०एम०ओ० की पोस्ट सिर्फ हरियाणा में 5 स्थानों के लिए है। ये पांच स्थान हैं, अम्बाला, फरीदाबाद, हिसार, करनाल और भिवानी। ये पोस्टें भी वहीं पर स्वीकृत हैं जहां पर हॉस्पीटल की बैडज की कैपेसिटी 200 या उससे अधिक है बाकी सभी जगह 120 या 200 से कम बैडज के हॉस्पीटल हैं इसलिए वहां पर पी०एम०ओ० की पोस्ट स्वीकृत नहीं है।

श्री अध्यक्ष : महाजन साहब, आप यह बताएं कि क्या अप्रैल 1996 से पहले वहां पर कोई पी०एम०ओ० था। यदि था तो क्या आपने उसको वहां से हटाया है।

श्री ओम प्रकाश महाजन : न वहां पर कोई पी०एम०ओ० था और न ही हमने किसी को वहां से हटाया है।

श्री सिरी कृष्ण हुड्डा : मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि आज से 10 महीने पहले के करीब मुख्य मंत्री जी मेरे हल्के के किलोई गांव में गए थे। वहां पर पहले पी०एच०सी० की बिल्डिंग थी, वह बाढ़ में बह गई थी। जब मुख्य मंत्री जी वहां पर गए थे तो वे वहां पर पी०एच०सी० की जगह पर सी०एच०सी० मन्जूर कर आये थे। इस वक्त वहां पर कोई स्टाफ नहीं है। न वहां पर कोई डॉक्टर, न कोई नर्स और न ही कोई कम्पांउडर है। मैं जानना चाहता हूं कि वहां पर स्टाफ कब तक भेजा दिया जायेगा।

श्री ओम प्रकाश महाजन : अध्यक्ष महोदय, ये वहां पर जा कर देख लें कि वहां पर कोई डॉक्टर आदि है या नहीं लेकिन मेरे पास जो रिकार्ड है उसके हिसाब से वहां पर डॉक्टर पोस्टिड है।

श्री सिरी कृष्ण हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री जी के नोटिस में पुनः लाना चाहता हूं कि वहां पर पी०एच०सी० पहले थी लेकिन पीछे बाढ़ के समय वह बिल्डिंग उसमें ढह गई थी। वहां पर अब न तो कोई स्टाफ है और न ही वहां पर यह चल रही है। जब मुख्य मंत्री जी गए थे तो उसको पी०एच०सी० की जगह सी०एच०सी० मन्जूर कर आये थे मैं जानना चाहता हूं कि वह

सी०एच०सी० की बिल्डिंग कब तक तैयार हो जायेगी और वहां पर कब तक स्टाफ पहुंच जायेगा। वहां कोई डाक्टर नहीं जाता।

श्री ओम प्रकाश महाजन : जहां पर जो डॉक्टर पोस्टिड है वह जाता है। हम सरप्राईज़ चैकिंग करते हैं, हमारी कमिश्नर महोदया, मैं खुद और डायरेक्टर साहब भी दौरे पर जाते हैं और उसी का परिणाम है कि अब सभी समय पर ड्यूटी पर जाते हैं और उनमें भी काम करने की भावना जागृत हुई है।

श्री सिरी कृष्ण हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब नहीं आ रहा।

श्री अध्यक्ष : माननीय हुड्डा साहब, आप यह बताएं कि वहां पर सी०एच०सी० कब मन्जूर हुई थी?

श्री सिरी कृष्ण हुड्डा : आज से 10 महीने पहले जब सी०एम० साहब वहां पर गए थे तो वे मन्जूर करके आये थे। वहां पर जो पहले पी०एच०सी० की बिल्डिंग थी वह बाढ़ में ढह गई थी। (विघ्न)

श्री धीरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा योग्य स्वास्थ्य मंत्री महोदय से एक जानकारी चाहूंगा। स्वास्थ्य मंत्री जी की जानकारी के लिए यह बताना चाहूंगा कि पी०एच०सी०, किलोई का दर्जा बढ़ा कर सी०एच०सी० किया गया है और मुख्य मंत्री जी ने इस हाउस में आश्वासन दिया था। हमारे माननीय साथी श्री सिरी कृष्ण हुड्डा जी ने हाउस में माननीय मुख्य मंत्री जी से इस बारे में अनुरोध किया था। यह रिकार्ड में है मुख्य मंत्री जी ने हाउस में बिल्डिंग बनवाने का आश्वासन दिया था कि कुछ समय बाद वहां पर बिल्डिंग का निर्माण करवा दिया जाएगा। उस आश्वासन के आधार पर मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से यह जानकारी चाहूंगा कि क्या वह बिल्डिंग सी०एच०सी० के लिए बनेगी या कि पी०एच०सी० के लिए बनेगी और जो स्टाफ वहां पर लगाया जाएगा वह पी०एच०सी० के नार्म का लगेगा या कि सी०एच०सी० के नार्म का लगेगा ?

श्री ओम प्रकाश महाजन : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया है और जो भी वायदा किया है वह 100 प्रतिशत पूरा होगा।

श्री सतपाल सांगवान : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के नोटिस में यह तथ्य लाना चाहूंगा कि दादरी का जो हॉस्पीटल नई बिल्डिंग में चालू किया गया है वह पिछले तीन-चार साल से बन्द पड़ा है। नई बिल्डिंग में न तो कोई एम०एस० डॉक्टर लगाया गया है और न ही वहां पर कोई डैंटल सर्जन नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही मैं उनसे यह जानकारी भी चाहूंगा कि जो नई बिल्डिंग बनाई गई है उसमें 50 बैडिड हॉस्पीटल चालू किया गया है जब कि यह पहले कण्डीशन थी कि वहां पर 100 बैडिड हॉस्पीटल बनाया जाएगा क्योंकि उसमें जगह सफिशेंट हो जाएगी और इसलिए उसमें 100 बिस्तर का अस्पताल कब से चालू हो जाएगा ?

श्री ओम प्रकाश महाजन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इनकी जानकारी के लिए यह बताना चाहूंगा कि जिस बिल्डिंग में अब हॉस्पीटल है वह पुराने हॉस्पीटल से करीब आधा-पौना किलोमीटर की दूरी पर है। यह जगह किसी ने दान में दी थी जिस पर बिल्डिंग बनाई गई है। नई बिल्डिंग में अस्पताल चालू हो गया है और जो मशीनरी वहां पर लगी हुई है वह चालू है और जो भी मशीनरी या इक्विपमैंट की वहां पर आवश्यकता होगी वह वहां पर उपलब्ध करवाई जाएगी। जहां तक डैंटल सर्जन का ताल्लुक है, हर पी०एच०सी० और सी०एच०सी० में डैंटल सर्जन लगे हुए हैं।

श्री सतपाल सांगवान : स्पीकर साहब, जो जानकारी दी गई है वह ठीक नहीं है दादरी में डैंटल सर्जन नहीं लगा हुआ है।

श्री ओम प्रकाश महाजन : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को मायूस नहीं करना चाहूंगा मेरे डिपार्टमैंट की तरफ से यह इन्फर्मेशन है कि हर पी०एच०सी० और सी०एच०सी में डैंटल सर्जन हैं। हर हॉस्पीटल में बेहतर इक्विपमैंट और स्टाफ दिया जाएगा। इसके साथ ही यह भी कहना चाहूंगा कि हर फैसिलिटी वहां पर उपलब्ध होगी। पुरानी सरकार की नासमझी के कारण मेवात में लोगों का ठीक ढंग से इलाज नहीं हो पाया था जिसके कारण कई लोगों की डैथ हो गई थी। परमात्मा की कृपा से अभी तक इस सरकार के आने के बाद कोई ऐसी वारदात नहीं हुई है क्योंकि डॉक्टरों को चौकन्ना कर दिया गया है। मेरे पास यह इन्फर्मेशन भी आ गई है कि किलोई में सी०एच०सी० की बिल्डिंग का प्लान बन चुका है।

श्री सिरी कृष्ण हुड्डा : मैं मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं।

श्री चन्द्र भाटिया : अध्यक्ष महोदय, फरीदाबाद के अन्दर बादशाह खान हॉस्पीटल के लिए एक नए हॉस्पीटल की बिल्डिंग बनाई जा रही है। इस बिल्डिंग के बारे सदन में सवाल भी किया गया था और मंत्री जी ने जबाव दिया था तथा इस बिल्डिंग का काम शुरू किया गया था। कुछ समय तक काम चला लेकिन उसके बाद फिर काम बन्द हो गया है। मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि इस अस्पताल की बिल्डिंग कितने समय तक तैयार हो जाएगी और जो काम बन्द पड़ा हुआ है वह किस कारण से बन्द पड़ा हुआ है ?

श्री ओम प्रकाश महाजन : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है वह प्रश्न से सम्बंधित नही है। जैसा कि आपको भी पता है यह विभाग काफी बड़ा है और इसके सभी आंकड़े याद नहीं रह सकते हैं। अगर माननीय सदस्य इसका जवाब जानना चाहते हैं तो मुझे यह प्रश्न अलग से लिख कर दे दें तो मैं इनको इसका जवाब दे दूंगा।

श्री जय सिंह राणा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि पिछले बजट सैशन के वक्त तरावड़ी में सी०एच०सी० के लिए 24 लाख रुपए की मन्जूरी हुई थी और इन्होंने उसके बारे में बताया था कि चालू वित वर्ष में इसका काम कम्प्लीट कर दिया जाएगा। लेकिन आज तक इस बारे में कोई भी काम वहां पर नहीं किया गया है। मंत्री जी यह बताएं कि वहां पर काम न होने का क्या कारण है और कब तक यह काम वहां पर शुरू करवा दिया जाएगा ?

श्री ओम प्रकाश महाजन : अध्यक्ष महोदय, अगर मैंने पहले ऐसे किसी सवाल का जवाब दिया होगा तो मैंने तथ्यों पर ही कहा होगा। आज हरियाणा प्रदेश में कई सी०एच०सी० और पी०एच०सी० की बिल्डिंगज़ बनाई जा रही हैं। इन्होंने बताया कि वहां पर बिल्डिंग नहीं बन रही है तो वहां पर कोई टैक्नीकल प्रोब्लम होगी तभी वहां पर बिल्डिंग नहीं बनाई जा रही है। हमारी सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है कि अगर हमें किसी ने वोट नहीं दिए हैं तो हम वहां पर काम नहीं करवाएंगे। हम सभी जगह पर काम करवाएंगे ऐसी हमारी सरकार की मंशा है।

Water-logging

*531. **Shri Ram Phal Kundu :** Will the Minister of State for Irrigation be pleased to state the steps taken or proposed to be taken to check water-logging in the State ?

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री हर्ष कुमार) : राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में, जो सेम से बुरी तरह प्रभावित हैं, भूमिगत पानी का स्तर कम करने के लिये हरियाणा राज्य लघु सिंचाई एवं नलकूप निगम ने 115 वर्टीकल ड्रेनेज नलकूप लगाये हैं। कृषि विभाग हरियाणा ने नीदरलैंड सरकार की सहायता से गोहाना व कलायत में लगभग एक-एक हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल में सब सरफेज़ ड्रेनेज के निर्माण और रखरखाव की दो योजनाएं आरम्भ की हैं।

हरियाणा राज्य में भूमिगत पानी के स्तर को ऊपर आने की रोकथाम के प्रति मास्टर प्लान तैयार करने के लिये हरियाणा सरकार ने हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के उप-कुलपति की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय विशेषज्ञों की एक कमेटी का गठन किया है।

श्री शम फल कुंडू : अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के सफीदों में कुछ एरिया सेम से पूरी तरह से ग्रस्त है उस बारे में सरकार क्या कदम उठाने जा रही है ताकि वह सेम खत्म हो सके। अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रश्न पूछा था वह और था और जो लिखा गया है वह कुछ और है।

श्री हर्ष कुमार : अध्यक्ष महोदय, जो इन्होंने सवाल पूछा था उसका तो जवाब दे दिया है। जहां तक सफीदों की बात है तो इन्होंने कल भी सेम के बारे में प्रश्न पूछा था और कल राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलते हुए अपनी बात कही थी तथा इसका जवाब दे दिया गया था। मैं इनको बताना चाहूंगा कि सेम के मसले पर दो तरह की योजनाएं हैं एक तो वर्टिकल योजना और दूसरी होरीज़ैंटल योजना है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कुंडू जी को बताना चाहूंगा कि सोनीपत में भी 12 किलोमीटर का क्षेत्रफल है जहां पर सेम की समस्या है। (विघ्न) कुंडू जी, आपके सफीदों हल्के में जिन-जिन गांवों में जो भी एरिया सेम से प्रभावित हों, आप उसके बारे में बिस्तार से लिखित में भिजवा दें। वहां पर जो भी संभव उपाय होगा, वह सरकार जल्दी से जल्दी करा देगी।

श्री मनीराम : स्पीकर साहब, मैं आपकी मार्फत मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि सिरसा जिले में रोड़ी और दड़बेकला हल्के में जो तीस या चालीस गांवों में सेम आयी हुई है, उनके बारे में सरकार क्या कोई कदम उठाने जा रही है ?

श्री हर्ष कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मनीराम जी को बताना चाहूंगा कि यह जो सेम की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है तो इसके बारे में सरकार और आदरणीय मुख्य मंत्री जी बहुत चिंतित और प्रयत्नशील है। (विघ्न) जहां तक मनीराम जी ने सिरसा जिले में सेम की बात कही तो यह समस्या आज एक ऐसी स्टेज पर है जिसको लेकर हमारे विशेषज्ञ भी चिंतित हैं और वे इसके शोध में लगे हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, पिछले दस बारह साल से किसी भी सरकार ने इस समस्या को गंभीरता से नहीं लिया है इसलिए यह समस्या आज हर साल दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। इसका बढ़ने का कारण यही है कि पिछले दस बारह साल से जो नहरे हैं उनकी मरम्मत का काम नहीं हुआ है और उनमें से सीपेज लगातार हो रही है इसलिए उनके साथ लगते हुए इलाकों में जैसे सिरसा डिस्ट्रिक्ट में जो कि रेतीला इलाका है में ओवर इरीगेशन से सेम बढ़ी है। इस समस्या का लार्ज स्केल पर पहुंचने का कारण यही है कि जो इलाके हैड की तरफ पड़ते हैं वहां के किसानों ने न तो प्रशासन की परवाह की और न ही टेल की तरफ पड़ने वाले किसानों के इलाकों की परवाह की और वे बिना कोई परवाह किए ओवर इरीगेशन करते चले गए इसलिए सेम की समस्या बढ़ती चली गयी।इस सरकार ने कार्य भार संभालते ही इस बारे में एक उच्च स्तरीय कमेटी बनायी है। पहले इस कमेटी की अध्यक्षता श्री के०एस०पाठक जो कि इरीगेशन डिपार्टमैंट में इंजीनियर इन चीफ एवं बाद में सिंचाई सलाहकार होते थे, ने की। परन्तु परमात्मा की इच्छा से और हमारी बदकिस्मती से जब उनका स्वर्गवास हो गया तो इस कमेटी का अध्यक्ष

[श्री हर्ष कुमार]
हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के उपकुलपति को बनाया गया। इस समिति की पिछले दिनों एक मीटिंग माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा की अध्यक्षता में 13-1०-97 को हुई जिसमें यह निर्णय लिया गया कि सारे संबंधित विभाग अपने कार्यों से संबंधित भूजल की बढ़ती हुई स्तर की समस्या की रोकथाम के लिए सब-प्लैन बनाएंगे और ये विभाग वर्ष 1997-98 और 1998-99 के लिए प्रस्तावित गतिविधियों के ऐक्शन प्लान भेजेंगे जो कि विभिन्न विभागों में बनाये जा रहे हैं।

Up-Gradation of Schools

***558. Shri Mani Ram :** Will the Minister for Education be pleased to state the districtwise number of schools, if any, upgraded from Primary to Middle, Middle to High and High to 10+2 in the State during the year 1997-98 ?

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : सूची सदन के पटल पर रखी जाती है।

सूची

वर्ष 1997-98 में जिलावार स्तरोन्नत किए गए स्कूलों की संख्या

जिला	प्राईमरी से मिडल	मिडल से हाई	हाई से सी०सै०
1	2	3	4
हिसार	11	9	14
करनाल	9	8	7
कैथल	5	7	10
जीन्द	7	14	7
महेन्द्रगढ़	13	9	11
अम्बाला	5	1	9
गुड़गावां	9	6	7
फरीदाबाद	7	7	15
पानीपत	3	3	3
सोनीपत	5	8	10
रोहतक	4	6	9
रिवाड़ी	10	8	5
कुरुक्षेत्र	3	2	10
यमुनानगर	5	7	7
पंचकूला	1	2	-
भिवानी	13	16	19
सिरसा	2	7	-
कुल:	**112**	**120**	**143**

श्री मनी राम : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो सूची पटल पर रखी है वह * * * * है।

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : मनी राम जी ने जो झूठ शब्द कहा है उसे रिकार्ड न किया जाए।

श्री मनी राम : अध्यक्ष महोदय, सिरसा जिले के साथ इसमें बड़ा भेदभाव हुआ है आपने सूची देखी ही है सिरसा जिले में एक भी सीनियर सैकेण्डरी स्कूल अपग्रेड नहीं किया गया इसके बारे में मंत्री जी बताएं।

श्री राम विलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं मनीराम जी से कहना चाहता हूं कि इस सदन में सब लोगों ने स्वीकार किया कि इस बार जितने स्कूलों का दर्जा बढ़ाया गया है, उतना कभी नहीं बढ़ाया। एक विद्यालय ऐसा बनाने की योजना हम बना रहे हैं जिसमें इन साथियों को पढ़ाने का प्रबन्ध हो। (हंसी) माननीय सदस्य ने कह दिया कि हमने सूची गलत दे दी। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा में पिछले साल आजादी की स्वर्ण जयंती मनाई गई उसके अवसर पर शिक्षा के विस्तार के लिए 375 विद्यालयों का दर्जा बढ़ाया गया और जहां-जहां से मांग थी और जो विद्यालय शर्तें पूरी करते थे उनका दर्जा बढ़ाया। हमने हरियाणा के सभी जिलों में, चुनाव क्षेत्र के हर हिस्से में विद्यालयों का स्तर बढ़ाया है। इस सूची को यदि मनीराम जी को पढ़ने में कठिनाई है तो मैं पढ़कर सुना देता हूं हिसार जिले में 11 प्राइमरी से मिडिल 9 मिडिल से हाई और 14 हाई से 10 जमा 2, करनाल में 9 प्राइमरी से मिडिल, 8 मिडिल से हाई और 7 हाई से सीनियर सैकेण्ड्री, कैथल में 5 प्राइमरी से मिडिल, 7 मिडिल से हाई और 10 हाई से 10 जमा दो,जींद में 7 प्राइमरी से मिडिल, 14 मिडिल से हाई और 7 हाई से 10 जमा दो, महेन्द्रगढ़ में 13 प्राइमरी से मिडिल, 9 मिडिल से हाई और 11 हाई से 10 जमा दो, अम्बाला में 5 प्राइमरी से मिडिल, 1 मिडिल से हाई व 9 हाई से 10 जमा दो, गुड़गांव में 9 प्राइमरी से मिडिल, 6 मिडिल से हाई ओर 7 हाई से दस जमा दो, फरीदाबाद में 7 प्राइमरी से मिडिल, 7 मिडिल से हाई और 15 हाई से 10 जमा दो, पानीपत में 3 प्राइमरी से मिडिल, 3 मिडिल से हाई और 3 हाई से 10 जमा दो, सोनीपत में प्राइमरी से मिडिल 5, मिडिल से हाई 8 व हाई से 10 जमा दो 10, रोहतक में प्राइमरी से मिडिल 4, मिडिल से हाई 6 व हाई से 10 जमा दो 9, इसमें चौधरी सिरी कृष्ण लाल हुड्डा के चुनाव क्षेत्र में एक दस जमा दो किया और सांपला का दर्जा बढ़ाया और चौधरी बलवंत सिंह मायना जी व चौधरी धीरपाल सिंह जी ने जहां कहा उन सब विद्यालयों में दर्जा बढ़ाया। इस प्रकार रिवाड़ी में 10 प्राइमरी से मिडिल, 8 मिडिल से हाई व 5 हाई से दस जमा दो किए, कुरुक्षेत्र में 3 प्राइमरी से मिडिल 2 मिडिल से हाई व 10 हाई से दस जमा दो किए।

जिसमें माननीय साथी श्री अशोक कुमार जी के चुनाव क्षेत्र थानेसर का ज्योतिसर स्कूल अपग्रेड करके प्लस टू किया है। (विघ्न) मनीराम जी यह जो लिखा हुआ रिकार्ड है यह तो पढ़ा जायेगा। मैं जो बात कह रहा हूं कि यमुनानगर में पांच प्राइमरी स्कूल को मिडिल, 7 मिडिल स्कूल को हाई स्कूल और सात हाई स्कूल को सीनियर सैकेन्डरी स्कूल अपग्रेड किया गया। इसी तरह पंचकूला क्योंकि नया जिला था इसलिए उसमें एक स्कूल प्राईमरी से मिडिल, दो मिडिल से हाई और भिवानी में 13 प्राईमरी स्कूलों को मिडिल, 16 मिडिल स्कूलों को हाई स्कूल और 19 हाई स्कूलों को सीनियर सैकेंडरी स्कूलों का दर्जा दिया गया इसी तरह सिरसा में दो प्राईमरी स्कूलों को मिडिल और सात मिडिल स्कूलों को हाई स्कूल का दर्जा दिया गया तथा मोरीवाला गांव का मिडिल स्कूल जिसकी 32 सालों से मांग चली आ रही थी और उस मांग को यह पूरा नहीं कर पाये वह हमने कर दिया जोकि मनीराम जी के हल्के में पड़ता है। (विघ्न)

श्री मनीराम : मोरीवाल स्कूल मेरे हल्के में नहीं पड़ता।

श्री अध्यक्ष : मनीराम जी, आप तो कह रहे थे कि सिरसा जिले में कोई स्कूल अपग्रेड नहीं किया गया। (विघ्न)

श्री धीरपाल सिंह : स्पीकर सर, चौधरी मनीराम जी ने हाई स्कूल को सीनियर सैकेंडरी स्कूल का दर्जा दिये जाने के बारे में पूछा है। मंत्री महोदय उस सवाल का जवाब तो दे ही नहीं रहे।

श्री मनीराम : स्पीकर सर, भिवानी जिले में तो 19 स्कूलों को सीनियर सैकेंडरी स्कूलों का दर्जा दिया गया और सिरसा जिले में निल (शून्य)। इसी के बारे में मैं पूछना चाहता हूं। आप इस बारे में चाहे श्री गणेशीलाल जी से पूछ लें।

खाद्य तथा पूर्ति मंत्री (श्री गणेशी लाल) : स्पीकर सर, आदरणीय सदस्य ने मेरा नाम लिया है। इसलिए मेरा फर्ज है कि मैं उनका जवाब दूं।

श्री अध्यक्ष : नहीं। आप बैठिये।

श्री रामबिलास शर्मा : स्पीकर सर, मैं मनीराम जी को बताना चाहता हूं कि यह तो कह रहे थे कि एक स्कूल को भी हाई स्कूल का दर्जा नहीं दिया। हमने तो सात मिडिल स्कूलों को हाई स्कूल का दर्जा दिया है तथा हाई स्कूल से सीनियर सैकेंडरी स्कूल का दर्जा देने के लिए कुछ नार्म्ज होते हैं कि उस स्कूल में पहले हाई स्कूल की कक्षायें पढ़ाई जानी चाहियें तथा पूरा भवन होना चाहिये साथ में खेल का मैदान होना चाहिये। फिर भी मनीराम जी के मामले पर हम विचार कर लेंगे ये जिस भी विधालय का स्तर बढ़ाने के लिए हमें कहेंगे हम उस विधालय के बारे में नार्म्ज के मुताबिक विचार कर लेंगे।

वॉक-आऊट

श्री रामबिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, चौधरी मनीराम जी ने पूरे वर्ष के अंदर किसी भी विद्यालय का दर्जा बढ़ाने के लिए हमें नहीं कहा है। अगर किसी विद्यालय का दर्जा बढ़ाने के लिए अब ये कहेंगे तो हम उस पर विचार कर लेंगे। (शोर)

श्री मनीराम : अध्यक्ष महोदय, * * * * *

श्री अध्यक्ष : श्री मनीराम जी जो कुछ भी बोल रहे हैं, वह रिकार्ड न किया जाए। (शोर)

श्री सतपाल सांगवान : अध्यक्ष महोदय, 20 सालों में इनको भिवानी दिखायी नहीं दिया, अब ये सिरसा की बात कर रहे हैं। (शोर)

श्री भागी राम : अध्यक्ष महोदय, * * * * *

श्री अध्यक्ष : श्री भागी राम जी जो कुछ कह रहे हैं, वह रिकार्ड न किया जाए।

श्री मनी राम : अध्यक्ष महोदय, अगर आप हमें बोलने नहीं देंगे तो हम एज ए प्रोटैस्ट सदन से वॉक-आउट कर जाएंगे।

(इस समय इनेलोद (रा) पार्टी के विधायक श्री मनी राम व श्री भागी राम जी सदन से वॉक-आउट कर गए)

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

State Highways

*561. **Shri Anil Vij** : Will the Minister for P.W.D. (B&R) be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to widen/ strengthen the State Highways; if so, the details thereof ?

Public Works Minister (Shri Dharam Vir Yadav) : Yes, Sir. Administrative approval for widening of 437.44 Kms. and strengthening of 128.05 Kms. of State Highways have been issued at a cost of Rs. 1112.68 lac and Rs. 503.51 lac respectively.

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं चूंकि मंत्री जी ने अपने जवाब में बताया है कि स्टेट हाई-वे की 437.44 कि०मी० की वाइडनिंग और 128.05 कि०मी० की स्ट्रैथनिंग की एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल दे दी गई है। क्या मंत्री जी डिटेल बताने की कृपा करेंगे कि कौन-कौन सी सड़कों पर यह पैसा लगाया जाएगा ?

श्री धर्मवीर यादव : अध्यक्ष महोदय, इस के लिए तो इनको अलग से प्रश्न पूछना पड़ेगा। फिर भी मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि इनसे संबंधित जो एरिया है, वह अम्बाला से जगाधरी स्टेट हाई-वे का है जिस पर हम स्ट्रैथनिंग और वाइडनिंग का काम करेंगे।

श्री अशोक कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि लाडवा से करनाल वाली रोड जो बुरी तरह से टूटी हुई है क्या उसको भी ठीक करने व चौड़ी करने की कोशिश करेंगे ?

श्री धर्मवीर यादव : अध्यक्ष महोदय, लाडवा से करनाल वाली सड़क को भी हम अवश्य ही ठीक व चौड़ा करेंगे।

श्री धर्मवीर गाबा : Mr. Speaker, Sir, the question put by Mr. Vij is-

> "Will the Minister for P.W.D. (B&R) be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to widen/strengthen the State Highways; if so, the details thereof ?"

अब जैसे कि विज साहब ने एक प्रश्न पूछा तो उनको कहा गया कि इसके लिए तो अलग से प्रश्न पूछना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, क्या आप जरूरी समझते हैं कि इसके लिए अलग से प्रश्न किया जाए। ये यहां पर क्या तैयारी करके आते हैं ? ये हमें यहां क्या मिसगाइड करने के लिए ही आते हैं ? आखिर यहां पर कोई ढंग की बात तो की जानी चाहिए। (शोर)

श्री धर्मवीर यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं इनको विस्तृत जानकारी पढ़कर सुना देता हूं।

Haryana Highway Upgradation Project

Following High Priority State Highways as detailed below are being proposed to be up-graded.

Sr. No.	Name of road.	Length (in Km.)
1.	Jagadhri-Ambala road.	50.40
2.	Titramour-Narwana-Jind-Hansi road.	107.10
3.	Hansi-Bhiwani-Dadri-Mohindergarh road.	102.90
4.	Panipat-Gohana-Rohtak-Jhajjar-Rewari-Bawal road (upto N.H.-8).	146.50
5.	Rohtak-Bhiwani road.	43.60
6.	Mohindergarh-Narnaul-Kotputli road.	63.70
7.	Ambala-Kaithal-Titramour road.	86.00
8.	Yamuna Nagar-Byepass-Yamuna Nagar-U.P. Border.	17.10
	Total :	627.30

श्री अध्यक्ष : गावा साहब अब तो आप मान गए कि ये आपसे ज्यादा तैयार होकर आते हैं।

श्री अनिल विज : मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वाइडनिंग एंड स्ट्रैंथनिंग ऑफ रोडज की एडमिनिस्ट्रेटिव एप्रूवल हो चुकी है अगर हो चुकी है तो क्या उनके लिए धन का प्रावधान कर दिया गया है अगर कर दिया गया है तो वह किन-किन वित्तीय संस्थाओं से उपलब्ध कराया जाएगा?

श्री धर्मवीर यादव : अध्यक्ष महोदय, एडमिनिस्ट्रेटिव एप्रूवल हो चुकी है और धन उपलब्ध कराने के बारे में वर्ल्ड बैंक से बातचीत चल रही है।

श्री ओम प्रकाश जैन : अध्यक्ष महोदय, पानीपत शहर जी०टी० रोड पर स्थित है उसका बहुत बुरा हाल है। मैंने पिछली बार भी कहा था कि पानीपत में बाई पास बनाने की बड़ी भारी जरूरत है। वहां पर मुख्य मंत्री जी गए थे उस समय उन्होंने यह विश्वास दिलाया था कि यहां पर बहुत जल्दी बाई पास बनाएंगे। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का वहां पर बाई पास बनाने का कोई विचार है।

श्री धर्मवीर यादव : अध्यक्ष महोदय, अभी ऐसा कोई विचार नहीं है।

श्री ओम प्रकाश जैन : अध्यक्ष महोदय, अगर वहां पर बाई पास नहीं बनाया जा सकता तो वहां पर एक मिनी बाई पास बनाया जा सकता है और उस पर सरकार का बहुत थोड़ा पैसा खर्च होगा। मेरी मंत्री जी से प्रार्थना है कि वहां पर एक मिनी बाई पास जल्दी बना दें ताकि लोगों को राहत मिल सके।

श्री धर्मवीर यादव : अध्यक्ष महोदय, वहां पर कोई बाई पास या मिनी बाई पास बनाने की कोई स्कीम नहीं है। पानीपत शहर का बहुत ज्यादा विस्तार हो चुका है इसलिए वहां पर बाई पास बनाना सम्भव नहीं है। लेकिन वहां पर ट्रैफिक का लोड देखते हुए एक एलीवेटिड ब्रिज बनाने की सरकार की स्कीम है।

श्री सतपाल सांगवान : अध्यक्ष महोदय मेरी कांस्टीच्यूएंसी में दो सड़के है। एक लोहरवाड़ा से झिंजर और दूसरी रोहतक से जयश्री। इन दोनों रोडज की इतनी बुरी हालत है कि इनके ऊपर आदमी

चल नहीं सकता बिल्कुल टूटी पड़ी हैं उनको रिपेयर के लिए आज तक टच नहीं किया गया है। मेरी मंत्री जी से प्रार्थना है कि आप उन रोडज की तरफ ध्यान दें और उनकी रिपेयर कराएं।

श्री धर्मवीर यादव : अध्यक्ष महोदय, उन सड़कों की धन उपलब्ध होने पर रिपेयर कर दी जाएगी।

शिक्षा मंत्री (श्री राम विलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, जब उन सड़कों का प्रीलिमनरी काम चल रहा होता है उस समय सांगवान साहब उन सड़कों के ऊपर से गुजर जाते हैं तो वे टूट जाती हैं फिर घूम जाते हैं तो फिर टूट जाती हैं। (हंसी)

Application received from NRIs

***490. Sh. Krishan Lal :** Will the Minister for Industries be pleased to state the total number of applications for setting up of Industries received from Non-resident Indians (NRIs) in the State during the year 1996-97 ?

उद्योग मंत्री (श्री शशि पाल मेहता) : वर्ष 1996-97 के दौरान 24 अनिवासी भारतीयों से आवेदन पत्र प्राप्त हुए।

श्री कृष्ण लाल : क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि 1996-97 में एन०आर०आईज० से कितनी एप्लीकेशंज यहां पर उद्योग लगाने के लिए प्राप्त हुई और उन पर क्या एक्शन लिया गया तथा उनका पूरे पते सहित ब्यौरा क्या है ?

श्री शशि पाल मेहता : अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1996-97 में एन०आर०आईज० से 24 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए थे। इनमें से हमने 9 को प्लाट दे दिए और 15 वापस कर दिए थे। इन्होंने उनके पते की डिटेल पूछी है, वह इस प्रकार है :-

1. Shri Balwant Singh Guraya, 10, Park Street Conventry CV 6, SAT England.
2. Shri Vinod Bhandari, 2 Bridgewate Court, Bridgewater Road, Wembley, HAQ IAU, United Kingdom.
3. Dr. Ish Anand, MD, 2621, North Moreland Boulevard, 1108, Shaker Heights, OHIO-441201403, USA.
4. Shri Deepak Jain, P.O. Box 759, Safat, 13008, Kuwait.
5. Mrs. Shobha Rani Bedi, 31, Bond Street, Ealing, London.
6. Shri Inder Pal Singh, 4932/119, Avenue Edmontor, L/Alberde, T6 L/4, A4, Canada.
7. Miss. Parveen Oborai, 14, Brewery Close, Wembley, Middx, HAO 2XA, U.K.
8. Shri Amatjit Singh Shahni, 39867, Fremount, 207, Fremount Callifornia-94538, U.S.A.
9. Shri Ajay Kumar Aggarwal, 178, SBI Colony, Paschim Vihar, Delhi.

The above persons have been allotted the plots. There are other 15 persons who have not been allotted the plots.

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय ने वर्ष 1996-97 के बारे में बताया कि इतनी एप्लीकेशंज एन०आर०आई०ज० की प्राप्त हुई और इतनों को प्लाट दिए गए। मैं जानना चाहूंगा कि क्या वर्ष 1997-98 के लिए भी इनको एन०आर०आई०ज० की एप्लीकेशंज प्राप्त हुई हैं। यदि हुई हैं तो उसका क्या ब्यौरा है ?

श्री शशिपाल मेहता : वर्ष 1997-98 में 12 एप्लीकेशंज हमें प्राप्त हुई हैं और इन 12 एप्लीकेशंज में से हम 6 को प्लाट एलाट कर चुके हैं, 4 की एप्लीकेशंज को वापस लौटा दिया है और दो एप्लीकेशंज अभी अंतिम फैसले के लिए पैंडिंग हैं।

Mr. Speaker : Questions hour is over.

नियम 45 के अधीन सदन की मेज़ पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Acute Shortage of Drinking Water

***506. Shri Kailash Chander Sharma :** Will the Minister for Public Health be peased to state--

(a) whether it is a fact that there is an acute shortage of drinking water in village Nizampur, Paira-Napla, Chhilro, Ghatashar, Basirpur, Karoli, Maroli, Dhancholi etc. of Nalwati area and at Godh Balah road in District Mahendergarh; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to provide drinking water through canal based water supply scheme in the above said villages ?

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री जगन नाथ) :

(क) गोद बलाहा रोड के साथ लगते गावों में पीने के पानी की कुछ कमी है, परन्तु नालावती क्षेत्र के गांवों में जल वितरण प्रर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

(ख) पानी की कमी वाले 21 गांवों की दो योजनाएं 2.25 करोड़ रुपये की लागत का कार्य प्रगति पर है। धनराशि की उपलब्धता पर इसको पूरा करने के लिए लगभग 2 वर्ष लगेंगे।

Classification of Scheduled Castes

***522. Shri Ramesh Kumar :** Will the Minister for Home be pleased to state--

(a) whether the candidates belonging to scheduled castes have been classified as A & B by the Government at the time of recruitment;

(b) if so, the names of the castes included in the said classification separately;

(c) the date on which the aforesaid policy of classification was implemented together with the criterion adopted for the purpose; and

(d) whether the classification as referred to in Part (a) above has been implemented in the process of recruitment of ASIs; if so, details thereof ?

गृह मंत्री (श्री मनी राम गोदारा) :

(क) हाँ।

(ख) 'ए' तथा 'बी' ब्लाक में वर्गीकृत जातियों के नाम निम्न लिखित हैं :-

	'ए' ब्लाक		'बी' ब्लाक
1.	अदधर्मी	1.	चमार
2.	बाल्मिकी, चूड़ा या भंगी	2.	जाटिया चमार
3.	बंगाली	3.	राहगरस
4.	बरार, बुरारोड	4.	रायगरस
5.	बालवाल	5.	रामदासिया या रविदासिया
6.	भूरीया या बावरीया		
7.	बाजीगर		
8.	बंजारा		
9.	चानाल		
10.	दागी		
11.	धरेन		
12.	देहा, ढ़या या ढेया		
13.	भोगरी, धारगरी या सींगी		
14.	धानक		
15.	डुमना, महाशा या डूम		
16.	गगरा		
17.	गचीला या गांदील, कानडेले		
18.	कबीरपंथी या जुलाहा		
19.	खटीक		
20.	कोडी या कोली		
21.	भारीजा या भारेचा		
22.	मजहबी		
23.	मेघ		
24.	नट		

[श्री मनीराम गोदारा]

25. ओड
26. पासी
27. पेरमा
28. फेरीरा
29. सनहाई
30. सनहाल
31. सांसी, भेडकूट या मामेश
32. सांसी
33. सपेला
34. सांरेरा
35. सिलीगर
36. सिरकीबंद

(ग) वर्गीकरण की नीति मुख्य सचिव हरियाणा सरकार के पत्र क्रमांक 22/55/90-3जी०एस०-III दिनांक 9-11-1994 के अनुसार लागू की गई थी।

(घ) हाँ, सहायक उप निरीक्षक के कुल 150 पदों में से केवल 30 पद अनुसूचित जाति के हिस्से में आते हैं। इन 30 पदों का अनुसूचित जाति 'ए' तथा 'बी' ब्लाक में निम्नानुसार पहले ही विभाजन किया जा चुका है।

(i) ब्लाक 'ए' 15
(ii) ब्लाक 'बी' 15

Eradication of Leprosy

***511. Shri Dharam bir Gauba :** Will the Minister for Health be pleased to state whether any time bound programme for the eradication of Leprosy from the State has been received from the Central Government, if so, the details thereof ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश महाजन) : जी हाँ, हरियाणा राज्य को भारत सरकार से "संशोधित कुष्ठ रोग निवारण अभियान" (एम०एल०ई०सी०) का कार्यक्रम प्राप्त हुआ है जिस द्वारा कुष्ठ रोग 2000 ई० तक उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा गया है।

Providing of Compensation to the Farmers

***533. Shri Ramphal Kundu**
Dr. Verender Pal Ahlawat | Will the Minister for Revenue be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to give compensation to the farmers who could not sow their Rabi crops due to unseasonal rain in the year, 1997 ?

राजस्व मंत्री (श्री सूरजपाल सिंह) : बे-मौसमी वर्षा के कारण जो क्षेत्र विजाई किए बिना रह गया है, उसका ब्यौरा अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है क्योंकि विजाई जनवरी मध्य तक चल रही थी। क्षेत्रीय अधिकारियों से इस मामले में रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही मुआवजा देने के प्रश्न पर विचार किया जाएगा। इस बारे में उपायुक्तों को विशेष गिरदावरी करने की हिदायतें जारी की गई हैं। उन सभी किसानों जोकि खेतों में बाढ़ का पानी भरा रहने के कारण रबी फसल की विजाई नहीं कर सके, के आबियाना/तकावी ऋण तथा सहकारी ऋण 6 मास के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया जा चुका है।

Laying of Sewerage System in Ambala Cantt.

***562. Shri Anil vij :** Will the Minister for Public Health be pleased to state–

(a) the time by which the on-going construction work of sewerage system in Ambala Cantt. is likely to be completed; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Govt. to lay sewerage system in the remaining area of the aforesaid city ?

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री जगन नाथ) :

(क) 31-3-1998 तक।

(ख) रक्षा विभाग से मिलिट्री भूमि में बड़ी सीवर की लाईन लगाने की स्वीकृति आने तथा इस काम के लिए धनराशि उपलब्ध होने पर सीवरेज व्यवस्था के आगामी विस्तार पर विचार किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष : हाउस की जानकारी के लिए मैं यह बताना चाहूंगा कि कल माननीय सदस्य श्री धीरपाल सिंह जी के सुझाव पर यह तय हुआ था .....

श्री धीरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह सब का ज्वायंट सुझाव था।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, आप अभी अपनी सीट पर बैठिए। कल यह तय हुआ था कि अगर कोई भी सदस्य बोलना चाहे तो उसको 10 मिनट का समय दिया जाए। मैंने कल सदस्यों को यह आश्वासन दिया था कि हाउस चाहे रात के 10.30 बजे तक चलाना पड़े सभी सदस्यों को बोलने के लिए समय दिया जाएगा। किसी भी सदस्य को बोलने का मौका न मिले ऐसा नहीं हो सकता है। यह तो माननीय सदस्यों का अपना अधिकार है यदि वे बोलना चाहें तो बोलें। लेकिन आनरेबल मैम्बर्ज कल चले गए थे फिर भी अब तक गवर्नर एड्रैस पर 11 घंटे 43 मिनट्स की बहस हो चुकी है जिसमें हरियाणा लोक दल राष्ट्रीय 5 घंटे 29 मिनट्स, कांग्रेस आई० 3 घंटे 11 मिनट्स, हरियाणा विकास पार्टी 1 घंटा 27 मिनट्स, बी०जे०पी० 32 मिनट्स तथा इण्डिपैण्डैंट 1 घंटा 04 मिनट तक बोल चुके हैं।

श्री धीरपाल सिंह : स्पीकर सर, मैं आपके द्वारा अपनी कुछ आपत्तियां दर्ज करवाना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही सीरियस मामला है। चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा के बाद सभी सरकारों को आदेश दिए गए हैं कि वे आचार संहिता का उल्लंघन न करें। हरियाणा प्रदेश की सरकार कदम-कदम पर चुनाव आयोग के आदेशों की अवहेलना कर रही है।

श्री अध्यक्ष : धीरपाल सिंह जी, आप थोड़ी देर के लिए बैठें, मुझे एनाउंसमैंट करनी है।

सचिव द्वारा घोषणा

Mr. Speaker : Now, the Secretary will make an announcement.

Secretary : Sir, I have to inform the House that the Indian Electricity (Haryana Amendment) Bill, 1989 which was reconsidered and passed by the Haryana Legislative Assembly on the 19th November, 1996 has been assented to by the President.

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना का उत्तर देने के लिए समय बढ़ाना।

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I have received a Calling Attention Notice from Shri Om Parkash Chautala and thirteen others regarding the damage of crops due to untimely rain and hailstorms during the year 1997. It was admitted by me for 22nd January, 1998. Now, I have received a request from the Hon'ble Revenue Minister for extension of time for giving reply to the above Calling Attention Notice. I accept the request of the Hon'ble Minister and have extended the time for giving reply by the Revenue Minister.

सरकार द्वारा निर्वाचन आयोग के निर्देशों की अभिकथित उल्लंघना संबंधी मामला उठाना।

श्री धीरपाल सिंह : स्पीकर सर, मैं यह कह रहा था कि हरियाणा सरकार कदम-कदम पर चुनाव आयोग के आदेशों की अवहेलना कर रही है। On 18-1-1998, a letter was written by the Financial Commissioner & Secretary to Govt. Haryana, Planning Department regarding the release of funds under the 'Decentralised Planning'. इस के अधीन 5 करोड़ 50 लाख रुपये की राशि वर्तमान सरकार ने 19-01-1998 को अपने चहेते लोगों को नाजायज लाभ देने के लिए जारी की है, हमारी पार्टी इस कार्यवाही की कड़े शब्दों में निन्दा करती है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से दूसरी आपत्ति यह दर्ज करवाना चाहता हूं कि माननीय चुनाव आयोग ने प्रदेश के जहाज को प्रयोग न करने पर भी पाबन्दी लगाई है (विघ्न) मेरी जानकारी है कि हरियाणा सरकार के दो मंत्री साहब हरियाणा प्रदेश के जहाज को ले कर गए (विघ्न) यह मेरी जानकारी है, ऐसा मैंने कहा है। मेरी जानकारी यह है कि हरियाणा सरकार के दो मंत्रियों द्वारा हरियाणा प्रदेश के जहाज का प्रयोग किया गया जो चुनाव आयोग द्वारा जारी की गई आचार संहिता का उल्लंघन है।

श्री अध्यक्ष : इस जहाज का प्रयोग कब किया गया है ?

श्री धीरपाल सिंह : मेरी जानकारी के मुताबिक कल प्रयोग किया है। (विघ्न)

श्री भागी राम : अध्यक्ष महोदय, ... (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : भागी राम जी, सदन के कुछ नार्मज होते हैं उसके हिसाब से चलना चाहिए। आप उनकी बात सुनें। बीच में डिस्टर्ब न करें।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, चौधरी धीरपाल जी ने कहा कि हरियाणा के वित्तायुक्त द्वारा कोई फंड दिया गया है। मैं इनको बताना चाहूंगा कि चुनाव आयोग ने जो हिदायतें दी हैं उस बारे में हमारी सरकार और हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत सचेत हैं ताकि चुनाव आयोग की हिदायतों का उल्लंघन न हो। आज तक चुनाव आयोग द्वारा हमारी सरकार की किसी गतिविधि और किसी कार्य के बारे में कोई आपत्ति नहीं की गई है। अध्यक्ष महोदय, मैं इनको बताना चाहता हूं कि चुनाव के समय में भी सरकार चलती है और जो पहले के कार्य चल रहे हैं, जो गतिविधियां पहले से चल रही हैं उन पर कोई चुनाव आयोग पाबन्दी नहीं लगाता है। वित्तायोग के बारे में जो इन्होंने कहा है मैं इनको बताना चाहूंगा कि जब हमारी सरकार बनी थी तो मुख्यमंत्री जी ने कमिटमैंट की थी कि हम हरियाणा के हर कर्मचारी को वेतन केन्द्र के वेतन के अनुसार ज्यों का त्यों देंगे और वह हमने दिया भी है। जो सरकार की पहले की योजनाएं थी जो गतिविधियां होती हैं वे तो चलती रहती हैं। इन्होंने बोलते हुए कहा कि दो मंत्री हवाई जहाज से गए। मैं इनको बताना चाहूंगा कि दो मंत्री नहीं बल्कि चार मंत्री गए थे। इस जहाज का नम्बर वी०टी०55 था यह ओम प्रकाश जिन्दल का जहाज है। हम उस जहाज में हिसार और भिवानी गए थे इनको पता नहीं क्या मुसीबत हो रही है। मैं इनको यह भी बताना चाहता हूं कि हम 16 फरवरी को गए थे। सरकारी जहाज पर तो हमने कपड़ा डाल रखा है। उस जहाज का दुरुपयोग तो दूर रहा हम सदुपयोग भी नहीं करेंगे। जिस स्टेट प्लेन की ये बात कर रहे हैं तो उस बारे में मैं इनको यह बताना चाहता हूं कि वह जहाज श्रीमन् गुलजारी लाल नंदा, भारत के भूतपूर्व प्रधान मंत्री जी की अस्थियां लेने अहमदाबाद गया था। धीरपाल जी आप जो जानकारी लेकर आएं कृपया ठीक जानकारी लेकर आया करें।

श्री धीरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, श्रीमन् नन्दा जी के प्रति हमारी बहुत श्रद्धा है। मैं इनसे ज्यादा उनका सम्मान करता हूं। अभी मंत्री जी कह रहे थे कि हमने सरकारी जहाज पर कपड़ा डाल रखा है। अब ये कह रहे हैं कि जहाज अहमदाबाद गया था।

कृषि मंत्री (श्री कर्ण सिंह दलाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहने के लिए खड़ा हुआ हूं कि इसमें चौधरी धीरपाल जी का कोई कसूर नहीं है। मैं इनको यह बताना चाहता हूं कि जब इनकी सरकार होती थी तो ये लोग चुनाव आयोग की हिदायतों का उल्लंघन करते थे, चौधरी देवी लाल जी उल्लंघन करते थे, चुनाव में सरकारी जहाज का इस्तेमाल करते थे। आप लोग चुनाव आयोग की हिदायतों का उल्लंघन करते थे हम नहीं करते हैं। मैं इनको बताना चाहता हूं कि आज की सरकार चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं कर रही है। कायदे कानून के मुताबिक जो काम हैं, वह आज की सरकार कर रही है। (विघ्न)

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना

डॉ० वीरेन्द्र पाल अहलावत : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हाउस को बताना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : नहीं नहीं, वीरेन्द्र पाल जी, आप बैठिए। (विघ्न)

डॉ० वीरेन्द्र पाल अहलावत : अध्यक्ष महोदय, आज का इंडियन एक्सप्रेस अखबार है जिसमें एक बहुत ही सीरियस मैटर है। (विघ्न)

श्री धीरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक कालिंग अटेंशन मोशन था।

श्री अध्यक्ष : आपके कालिंग अटेंशन मोशन के बारे में मैंने रिप्लाई देने के लिए टाईम एक्सटैंड कर दिया है और अब गवर्नर एड्रैस पर डिसकशन रिज्यूम होगी।

श्री रणदीप सिंह सुर्जेवाला : स्पीकर सर, मेरा भी एक काल अटेंशन मोशन फसलों की बरबादी के बारे था, उसका क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष : सुर्जेवाला साहब, आप बैठिए। आपका यह मोशन डिसअलाऊ हो गया है। (विघ्न)

बैठक का स्थगन

डॉ० वीरेन्द्र पाल अहलावत : अध्यक्ष महोदय, इससे पहले आप मेरी बात सुनिए क्योंकि यह बहुत ही अहम मसला है। * * * *

श्री अध्यक्ष : अब ये जो भी बोल रहे हैं, उसको रिकार्ड न किया जाए। (विघ्न) आप सभी बैठें।

श्री अशोक कुमार : अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति के आदेशों की अवहेलना की गयी है। यह बहुत ही सीरियस मैटर है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : अशोक जी, आप बैठिए।

श्री धीरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही सीरियस मामला है। इसलिए इसको आप देखें। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : अब जो भी धीरपाल जी बोल रहे हैं, वह रिकार्ड न किया जाए।

श्री धीरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, * * * *(विघ्न)

श्री रणदीप सिंह सुर्जेवाला : अध्यक्ष महोदय, * * * *

Mr. Speaker : Dr. Virender Pal, I warn you as well as Shri Randeep Singh Surjewala. (Interruption) You please take your seat now. Dr. Virender Pal Ahlawat, Ji, please take your seat. I warn you, otherwise I will have to name you.

(Dr. Virender Pal Ahlawat continued speaking without permission of the Speaker)

Mr. Speaker : Dr. Virender Pal Ahlawat ji, I again warn you. Please take your seat.

(Dr. Virender Pal Ahlawat continued speaking without permission of the Speaker and there was grave disorder in the House.)

Mr. Speaker : The House is adjourned for 10 minutes.

(The Sabha then adjourned for 10 minutes and reassembled at 10.56 a.m.)

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

सदस्य का नाम लेना

श्री रणदीप सिंह सुर्जेवाला : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए * * * * * (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : जो सुर्जेवाला जी बोल रहे हैं उसको रिकार्ड न किया जावे।

डॉ० वीरेन्द्र पाल अहलावत : अध्यक्ष महोदय, आज के अखबार की एक खबर है कि हमारे सदन के अंदर एक बिल पेश किया गया था (विघ्न) * * * * *

श्री अध्यक्ष : कुछ भी रिकार्ड न किया जाये। डॉ० साहब जो आपके मन में है वह तो हम नहीं करेंगे। आप हाउस की कार्यवाही को आराम से चलने दें।

श्री जयसिंह राणा : हमारे मन में कुछ नहीं है हमारी रिक्वैस्ट है कि आप हमारी बात सुन लें।

श्री अध्यक्ष : राणा जी आपको कल बोलने का मौका दिया था। रणदीप सिंह सुर्जेवाला जी ने जो कालिंग अटेंशन मोशन दिया था वह पहले ही डिसअलाउ हो चुका है। अब जीरो आवर खत्म हो चुका है। अब रामविलास शर्मा जी बोलेंगे। (विघ्न)

शिक्षा मंत्री (श्री राम विलास शर्मा) : स्पीकर सर, मेरी आपसे रिकवैस्ट है कि डॉ० वीरेन्द्र पाल आज के अखबार की खबर के बारे में कहना चाहते हैं, उनको उसके लिए बोलने का समय दिया जाये क्योंकि वह खबर मैंने भी पढ़ी है जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के वाईस चान्सलर की ऐपायंटमेंट के बारे में है।

11.00 बजे **डॉ० वीरेन्द्र पाल अहलावत :** अध्यक्ष महोदय, हम तो यह जानना चाहते हैं कि वाईस चांसलर की नियुक्ति की तारीख क्या है और राष्ट्रपति की अनुमति किस तारीख को हुई ? * * * * *

श्री अध्यक्ष : वीरेन्द्र पाल जी, जो कुछ कह रहे हैं, वह रिकार्ड न किया जाए। (शोर)

श्री राम विलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के जिस वाईस चांसलर की नियुक्ति के बारे में मेरे माननीय साथी जानना चाहते हैं वह दलित वर्ग का व्यक्ति है। (शोर)

श्री अशोक कुमार : अध्यक्ष महोदय, हम दलित वर्ग के एक व्यक्ति की नियुक्ति के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि जिस ढंग से यह नियुक्ति की गई है, उसके खिलाफ हैं। (शोर)

श्री राम विलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के वाईस चांसलर की नियुक्ति को हुए तो एक वर्ष हो गया है और इनको आज ध्यान आया है। राज्यपाल महोदय जो कि प्रदेश की युनिवर्सिटीज़ के चांसलर होते हैं वे ही वाईस चांसलर की नियुक्ति करते हैं और इसके लिए वाकायदा ऐक्ट बना हुआ है जिसकी स्पैसिफिक लाईन मैं पढ़कर सुना देता हूं कि –

" the Chancellor will appoint the Vice-Chancellor on the advice of the Government."

This is the clause. Hon'ble Chancellor of the Universities has appointed the Vice-Chancellor on the advice of the government. We gave the panel. The Chancellor is very much competent and this appointment is within his rights.

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

[श्री राम विलास शर्मा]
Nobody can challenge it. Dr. M.L. Ranga was appointed as Vice-Chancellor of Kurukshetra University by the Governor on the advice of the Government. Nothing is illegal in this action. This is what I wanted to submit.

डॉ० वीरेन्द्र पाल अहलावत : अध्यक्ष महोदय, मैं पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं। इन्होंने अभी अभी कहा है कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में एक दलित वर्ग के व्यक्ति की नियुक्ति की गई है। (शोर)

श्री अध्यक्ष : आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप केवल पर्सनल एक्सप्लेनेशन पर ही बोलें।

Shri Ram Bilas Sharma : What is the personal matter in it. I have nothing alleged against Dr. Virender Pal. I have not named him. (Interruptions). It is a fact that Dr. Ranga belongs to S.C. category. It is known to every body.

डॉ० वीरेन्द्र पाल अहलावत : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं * * * * *

Mr. Speaker : Nothing to be recorded. What Dr. Verender Pal has said without the permission of the Chair will not go on record. (Noise & Interruptions). Dr. Virender Pal Ji, I warn You. (Noise & Interruptions).

श्री राम विलास शर्मा : स्पीकर सर, दलित वर्ग के एक व्यक्ति को एक युनिवर्सिटी का वाईस चांसलर नियुक्त कर दिया गया है, यह बात मेरे इन भाईयों को बर्दाश्त नहीं हो रही है। (शोर)

श्री अध्यक्ष : मेरी सभी माननीय सदस्यों से प्रार्थना है कि सभी बैठ जाएं।

श्री अशोक कुमार : अध्यक्ष महोदय, हमारी तो केवल आपसे इतनी प्रार्थना है कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के वाईस चांसलर की नियुक्ति कब हुई और इस बारे में राष्ट्रपति की अनुमति कब मिली। वह बता दें (शोर) क्या आप हमें जवाब नहीं देना चाहते हैं ?

Mr. Speaker : Dr. Virender Pal ji, I again warn you (Noise & Interruptions) Mr. Surewala ji, I also warn you. (Noise & Interruptions). Dr. Virender Pal ji, I have warned you so many times. (Noise & Interruptions). Dr. Virender Pal Ji, I also name you. I request you to kindly leave the House. (Noise & Interrutptions).

(At this stage Dr. Virender Pal Ahlawat left the house)

वाक - आउट

श्री अशोक कुमार : अध्यक्ष महोदय, अगर आप हमें बोलने ही नहीं देंगे तो हम ऐज-ए-प्रोटैस्ट सदन से वॉक-आउट करते हैं।

(इस समय सदन में हलोद(रा) पार्टी के उपस्थित सभी सदस्य सदन से वॉक-आउट कर गए)

मुख्य मंत्री (श्री बंसी लाल) : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरी इन भाईयों से प्रार्थना है कि जो ईल्जाम इन्होंने लगाया है, उसका इनको कम से कम जवाब तो सुनकर के जाना चाहिए। ये ऐसे भागते क्यों हैं ? मैं तो 3-4 दिन से लगातार यह कह रहा हूं कि जवाब सुनने के वक्त तो ये भागेंगे।

*Not recorded as ordered by the Chair.

डॉ० वीरेन्द्र पाल अहलावत की नेमिंग को रद्द करना।

श्री रणदीप सिंह सुर्जेवाला : अध्यक्ष महोदय, * * * *

श्री अध्यक्ष : जो कुछ सुर्जेवाला जी कह रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाए।

मुख्य मंत्री (श्री बंसी लाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं धीरपाल जी को बुलाने गया था उन्होंने कहा है कि आप बीरेन्द्र पाल को वापिस बुला लो तो हम आ जाएंगे इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप बीरेन्द्र पाल को वापिस बुला लें ताकि वे हमारा जवाब सुन सकें।

श्री अध्यक्ष : यदि वे वापिस आना चाहते हैं तो आ जाएं, हमें कोई ऐतराज नहीं है।

सदस्य का नाम लेना

श्री रणदीप सिंह सुर्जेवाला : अध्यक्ष महोदय, * * * *

श्री अध्यक्ष : सुर्जेवाला जी जो कुछ कह रहे हैं, वह रिकार्ड न किया जाए। मैंने कल कहा था कि आप सबको बोलने का मौका दिया जाएगा लेकिन कल आप लोग सदन से वाक आउट कर गये। अब कल का दिन तो वापिस नहीं आ सकता। That is why, I cannot allow you to speak now. Please take your seat. Mr. Surjewala, I warn you not to speak without my permission.

(Shri Surjewala did not take his seat and continued speaking without permission of the Speaker)

Mr. Speaker : Mr. Surjewala, this is my last warning. Please take your seat. (Interruption) Mr. Surjewala, I request you to take your seat. . This is my last warning. Please take your seat, otherwise I will have to name you.

Shri Randeep Singh Surjewala : Speaker, Sir, * * * * *

Mr. Speaker : Nothing to be recorded. Mr. Surjewala, I again warn you and request you also to take your seat.

(Shri Surjewala did not take his seat and continued speaking without permission of the Speaker, despite his repeated warnings and requests for taking his seat).

Mr. Speaker : Mr. Surjewala, this is my last warning. Please take it seriously. You will be named, if you will act in this way.

(Shri Surjewala did not take his seat and continued speaking without permission of the Speaker)

Mr. Speaker : I name Mr. Randeep Singh Surjewala. I request him to leave the House.

(Shri Randeep Singh Surjewala left the House)

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

वाक-आउट

श्री दिलू राम : अध्यक्ष महोदय, हम अपनी पार्टी के सदस्य को मेम किए जाने के विरुद्ध वाक आउट करते हैं।

(इस समय श्री धर्मवीर गाबा को छोड़ कर इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के सदन में उपस्थित सभी सदस्य वाक आउट कर गए)

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं तो रोज ही कहता था कि जिस वक्त मैं जवाब दूंगा, उस वक्त ये मेरा जवाब सुनने के लिए यहां पर बैठे नहीं मिलेंगे। अब चौधरी धीरपाल जी को भी मैंने कहा कि वे हमारी बात सुनें और हमारा जवाब सुन कर जायें। वे इस समय सदन से बाहर हैं। हम उनकी इंतजार कर लेते हैं। जब तक वे नहीं आते हैं तब तक श्री रामविलास जी बोल लेंगे।

शिक्षा मंत्री (श्री राम विलास शर्मा) : स्पीकर साहब, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर 2 शिफ्टों में लगातार यहां पर चर्चा चल रही है। इस चर्चा में अब तक 30 माननीय विधायक हिस्सा ले चुके हैं। इन 30 विधायकों में 20 विधायक विपक्ष के हैं और 10 विधायक सत्तापक्ष के हैं। विपक्ष में कांग्रेस पार्टी और चौटाला साहब की लोकदल पार्टी के सदस्य हैं जबकि सत्ता पक्ष में हरियाणा विकास पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य और आजाद विधायक हैं। आपने सभी को बोलने का पूरा मौका दिया। स्पीकर साहब, कुल मिलाकर सब की बातचीत लिखी गई। कुछ माननीय साथियों ने अच्छे सुझाव भी दिए। इस अधिवेशन में कुछ साथियों ने मौलिक चर्चा भी की कि स्कूलों में अंग्रेजी को पहली कक्षा से ही प्रारंभ किया जाये। श्री धर्मवीर गाबा ने बताया कि गुड़गांव में कानून और व्यवस्था की स्थिति बड़ी चिंताजनक है तथा वहां पर आबादी के हिसाब से थानों में जवानों की संख्या कम है। चोरी की घटनाओं की भी चर्चा की गई। बहिन करतार देवी ने भी और डॉ० वीरेन्द्र पाल जी ने भी कहा कि हमारे यहां पर अंग्रेजी पहली कक्षा से पढ़ाई जानी चाहिए। हमारे माननीय साथी श्री निर्मल सिंह जी ने भी इस बात को कहा। श्री चन्द्र भाटिया जी के विधानसभा क्षेत्र में जो स्कूल अपग्रेड किये गये उसके लिए उन्होंने यहां पर धन्यवाद किया। इसके साथ ही साथ उन्होंने दो और स्कूलों का दर्जा बढ़ाने की बात भी कही। श्री अशोक कुमार जी ने कहा कि हमारे यहां पर पंजाबी को दूसरी भाषा का दर्जा दिया गया, परन्तु उस हिसाब से पंजाबी के अध्यापक नहीं लगाये गए। **(इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए)** डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि प्रदेश में हरियाणा विकास पार्टी और भारतीय जनता पार्टी गठबन्धन ने चौधरी बंसी लाल जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा और चुनावों के दौरान हम ने हरियाणा की 1 करोड़ 60 लाख जनता के सामने, देहात की चौपालों में और शहर के चौराहों पर, अपने चुनाव घोषणा पत्र में कुछ वायदे किये थे। हरियाणा के लोगों से, यहां की 36 बिरादरी से जो समर्थन हमें मिला था जो आशीर्वाद हमें मिला, उसकी वजह से आज यह सरकार बनी है। हमने सबसे पहले प्रदेश में "शराबबंदी" का वायदा किया था। डिप्टी स्पीकर साहब, आप भी जानते हैं कि इस सदन में विपक्षी पार्टी व कांग्रेस पार्टी ने भी हमारे इस वायदे का समर्थन किया कि शराब एक बुरी लत है तथा इसे बन्द किया जाना चाहिए। जब यह खून में दौड़ती है तो आदमी राक्षस प्रवृत्ति का हो जाता है। परिणामस्वरूप समाज में महिलाओं का सम्मान नहीं रहता है। गांधी बाबा जी ने कहा था कि अगर मैं एक दिन के लिए हिन्दुस्तान का प्रधानमंत्री बन गया तो सारे देश में शराब का नामोनिशान खत्म कर दूंगा और इसी प्रकार के

विचार स्वामी दयानन्द और नानक बाबा जी के थे। उपाध्यक्ष महोदय, भारत के संविधान निर्माताओं जिनमें से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी एक हैं, ने संविधान के निर्देशक सिद्धांतों में इस बात की चर्चा की है कि जो कल्याणकारी सरकार बने उसको शराब बंद कर देनी चाहिए तथा गौ-हत्या पर पाबन्दी लगानी चाहिए, ऐसे नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान में उपलब्ध हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हमने एक जुलाई, 1996 को हरियाणा प्रदेश में शराब की लानत को बन्द कर दिया। उसके बाद हमने कभी भी यह बात नहीं कही कि शराब पूर्णतया बन्द हो गई। डिप्टी स्पीकर सर, सामाजिक बुराई, सामाजिक कुरीति कानून बना देने मात्र से पूरी तरह से बन्द नहीं हुआ करती है। उपाध्यक्ष महोदय आप जानते हैं कि मेघालय की सरकार ने यह कहा है कि हरियाणा सरकार धन्य है जिस ने इस सामाजिक कुरीति को बन्द किया है। सालाना 800 करोड़ रुपये की सरकारी खजाने में हानि के बावजूद भी हमने इस को बन्द किया है। हमने जब सत्ता संभाली और उस वक्त जब हमने खजाने को खोला तो उसमें नोट नहीं मिले बल्कि एक परनोट मिला जिसमें यह लिखा था कि पिछली सरकार 3300 करोड़ रुपये का कर्ज छोड़ कर गई है। कोयला लिया लेकिन उसका पैसा अदा नहीं किया, कोयला रेल के द्वारा आता था तथा रेल का भाड़ा नहीं दिया। एन०टी०पी०सी० से बिजली लेते थे उसका बिल नहीं दिया। डिप्टी स्पीकर सर, "शराबबन्दी" कितनी सफल और कितनी असफल हुई, यह बात हरियाणा प्रदेश की जनता अच्छी तरह से जानती है। हमने 'शराबबंदी' का वायदा किया था और पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता इस बात को मानती है कि हमने अपने वायदे को पूरा किया है। पिछले विधानसभा सत्र में चौधरी भजन लाल जी ने सदन में कहा था कि भिवानी में शराब के कारण 12 आदमी मर गये। जब हमने उन 12 आदमियों के नाम और पते उनसे जानने चाहे तो उन्होंने सदन में कहा था कि जिस पर्ची पर उनके नाम और पते लिखे थे, वह पर्ची उनकी दिल्ली में कमीज़ की जेब में रह गई है। दो दिन के बाद सदन फिर शुरू हुआ तो हमने उन 12 आदमियों के नाम और गांवों के बारे में उनसे फिर जानकारी मांगी तो उन्होंने कहा कि उनकी टंग स्लिप हो गई थी, जुबान फिसल गई थी। उस वक्त सदन के नेता ने कहा था कि वे मुख्य मंत्री रहे हुए हैं, कोई बात नहीं है।

हरियाणा लोक दल (राष्ट्रीय) पार्टी के सदस्यों द्वारा सदन की कार्यवाही में भाग न लेना।

श्री उपाध्यक्ष : मैं सदन की सूचनार्थ यह बताना चाहूंगा कि मुख्य मंत्री जी ने श्री धीरपाल सिंह जी से सदन में आने के लिए जो आग्रह किया था, वह उन्होंने अस्वीकार कर दिया है और वे सदन में नहीं आ रहे हैं (विघ्न)

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री राम बिलास शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, आप इस बात से अन्दाजा लगा लें कि हमारे ये साथी कितना सच बोलते हैं। यह प्रजातन्त्र है, यहां पर जनता का राज है इसमें राजा प्रजा होती है। 5 साल बाद उसको अवसर मिलता है और डिप्टी स्पीकर सर, हर कुम्हार अपनी गधी को जलेबी खिलाना चाहता है लेकिन उसके लिए वह समर्थ नहीं होता है। डिप्टी स्पीकर सर, इस 'शराबबन्दी' के कारण पूरी दुनियां में हमारी तारीफ हुई है। इसके लिए सारी दुनिया ने चौधरी बंसी लाल जी को बधाई दी। साधुओं ने, संतों ने, आर्य समाज ने, सनातन धर्म ने, गुरूओं ने, सरकार के इस फैसले की मुक्त-कण्ठ से प्रशंसा की है। यहां तक कि शराब पीने वालों ने भी यह कहा कि अभी तक तो हम शराब पीना छोड़ नहीं पाये थे, लेकिन अब हमारा शराब पीना छूट गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि पूरी दुनिया ने चौधरी बंसी लाल जी को बधाई दी और उनके इस फैसले की मुक्त कण्ठ से सराहना की। डिप्टी स्पीकर सर, ये लोग आज

[श्री राम बिलास शर्मा]

तक कोई स्पैसिफिक बात सदन में या सदन के बाहर एस्टैब्लिश नहीं कर पाए। इन्होंने तो एक बात एस्टैब्लिश की कि सरकार ने बाहन जब्त करने शुरू कर दिये हैं। हमारी यह प्रतिज्ञा और संकल्प है कि 'शराबबंदी' होनी चाहिए। हमने यह फैसला दिल की गहराई से किया है। इस मामले में जितनी सख्ती करने की आवश्यकता होगी, वह हम करेंगे। डिप्टी स्पीकर सर, इनके ये इल्जाम हैं, ये तो बात को ट्विस्ट करने में माहिर हैं। इन्होंने यह भी कहा कि हरियाणा रोडवेज की बसों को कब्जे में ले लिया, प्राइवेट बसों को भी कब्जे में ले लिया। हमने कहा कि हां बसों को कब्जे में लिया है। हमने यह सब इस लिए किया है क्योंकि इट इज़ दि कम्पलीमैंट टू दि गवर्नमैंट। इनका आरोप है कि हमारी सरकार ने रास्ता बदल लिया। उपाध्यक्ष महोदय, हमने एक वायदा सबसे पहले पूरा किया जिसके कारण हरियाणा के पिछड़े क्षेत्र की महिलाओं ने, बहु-बेटियों ने और माताओं व बहिनों ने आज हरियाणा में बहुत राहत महसूस की है। इस वायदे को पूरा करने के लिए हमने चुनाव लड़ा था। आज इसी के कारण बहिन कान्ता देवी पहले से ज्यादा बहुमत लेकर हाउस में जीत कर आई हैं। हमें यह जो बहुमत मिला था उससे यह साबित होता है कि 'शराबबंदी' जनता की मांग थी।

इसके बाद उपाध्यक्ष महोदय, बिजली में सुधार हुआ है। इस बारे में भी माननीय साथियों ने कहा कि उनके समय में 24 घंटे बिजली मिलती थी। ये जिस आदमी का नाम लेते हैं, जिस समय की बात करते हैं, उस समय किस की सरकार थी ? मैं इनको बताना चाहता हूं कि उस वक्त बी०जे०पी० के समर्थन वाली सरकार थी। उस वक्त बिजली महकमे के मंत्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह, नारनौल वाले थे। उपाध्यक्ष महोदय, इतिहास झूठ नहीं बोल सकता है, दीवारें झूठ नहीं बोलती हैं और खण्डहर झूठ नहीं बोलते हैं। जिस ओम प्रकाश चौटाला की ये बात करते हैं उनका कार्यकाल 2 दिसम्बर 1989 से शुरू हुआ था और इनका कार्यकाल 173 दिन का रहा। तीन बार तो इन्होंने शपथ ली। एक बार तो ये दिल्ली से आते हुए रास्ते में ही रह गए। उस वक्त की इनकी जो उपलब्धि है, आज भी उस वक्त को याद करके आदमी आंसू बहाता है। उपाध्यक्ष महोदय, श्री बनारसी दास गुप्ता पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, फिर उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। उन पर भी इन्होंने गोली चलवाई। इनके कार्यकाल में सिर्फ महम में 24 आदमी मारे गए थे। ये लोग किसी दुर्घटना में नहीं मारे गए। इनको गोलियाँ मारी गई थीं। एक आदमी की जिद्द के कारण कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा यह सब हुआ। महम चौबीसी के आदमियों ने फैसला कर लिया है कि जो आदमी अपने आपको भगवान मानता है, जो आदमी किसी का भला नहीं कर सकता है, उस आदमी को हम वोट नहीं देंगे। जब यह बात चौटाला जी को पता चली तो वहां से इनकी पार्टी के टिकट पर जो अमीर सिंह पार्टी का उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा था, इन्होंने चुनाव को पोस्टपोन करवाने के लिए, जो कि 26 मई को होना था, उससे एक हफ्ता पहले ही उसकी हत्या करवा दी। उपाध्यक्ष महोदय, उस हत्या की जांच के लिए सैकिया कमीशन बनाया गया। उस कमीशन की इन्क्वायरी में जो इल्जाम था उस बारे में मैं यह कहना चाहूँगा कि मैं इल्जाम लगाऊं या कोई और लगाए, उससे इल्जाम साबित नहीं होता है। हरियाणा की जनता महान है, जागरूक है। उस कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि अमीर सिंह की हत्या ओम प्रकाश चौटाला और उसके आदमियों के इर्द-गिर्द घूम रही है। उपाध्यक्ष महोदय, इस हत्या में कुछ जानकारियां और भी हैं, लेकिन हम इन सारी बातों में जाना नहीं चाहते हैं। कुछ बातें हमारे उन मित्रों की तरफ से कही गयी हैं, इसलिए हमें इन बातों की चर्चा यहां पर करनी पड़ रही है। बिजली के उत्पादन के बारे में इनको एक बात की बड़ी तकलीफ हुई कि हम इसके लिए चौधरी बंसी लाल जी की प्रशंसा क्यों करते हैं ? उपाध्यक्ष महोदय, यह हरियाणा विकास पार्टी और बी०जे०पी० की मिली जुली सरकार है। लोगों ने यह सरकार बनायी है। इसलिए सरकार के मुखिया की जो उपलब्धि

होती है, वह सब लोग जानते ही हैं। परन्तु बिजली उत्पादन के बारे में हमारे इन मित्रों ने पूरे हरियाणा प्रदेश में एक होव्वा खड़ा किया कि हम बिजली का निजिकरण करने जा रहे हैं। जब हरियाणा की जनता ने इनकी यह बात स्वीकार नहीं की तो ये कहने लगे कि बिजली बोर्ड को भंग किया जा रहा है और परिणामस्वरूप अब बिजली बोर्ड के कर्मचारियों की छंटनी हो जाएगी। उपाध्यक्ष महोदय, 31 साल पहले हरियाणा बना था। कोई भी काम जो करेगा, वह उसी के खाते में जाएगा। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के टाईम में 24 लोगों की हत्याएं हुई, 110 बसें जलायी गयीं और 9 रेलवे स्टेशनों पर खड़ी हुई ट्रेनों को जलाया गया। लेकिन यदि चौधरी बंसी लाल जी ने अपने शासनकाल में हरियाणा प्रदेश के हर गाँव को सड़क से जोड़ा है या हर गाँव में बिजली पहुंचायी है तो उनका तो नाम होगा ही।जब इन मित्रों का समय आया था तब तो ये बिजली की तारें तक नहीं बदल सके थे, सड़कों पर पेची तक नहीं लगवा सके थे। अगर बंसी लाल जी ने कुछ कार्य किया है तभी तो हम उनकी बातें कहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आपने भी देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी स्वयं आज उनको बुलाने गए तथा स्पीकर साहब के ऑफिस का आदमी भी उनको बुलाने गया था। धर्मबीर गावा पुराने पार्लियामैंटेरियन होने के नाते यहां पर बैठे हुए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आपने इसी सदन में काफी समय उनको बोलने के लिए दिया । उनके बीस सदस्यों ने अपनी अपनी बातें यहां पर रखीं। सबने यही कहा कि हम बिजली को पूरी तरह से ऐस्टैब्लिश नहीं कर सके। उपाध्यक्ष महोदय, बिजली आज हरियाणा का जन-जीवन है। आज बिजली की प्राथमिकता है। पहले मुश्किल से 4-6 गांवों में बिजली होती थी, लेकिन प्रतिदिन बिजली कनैक्शंज लेने की संख्या अब बढ़ती ही जा रही है। आज बिजली के 29 लाख नये कंज्यूमर हो गए हैं। आज आटा पीसने के लिए भी बिजली चाहिए, दूध बिलौने के लिए भी बिजली चाहिए, कारखाना चलाने के लिए भी बिजली चाहिए, कमरे को ठंडा करने के लिए भी बिजली चाहिए, फ्रीज के लिए भी बिजली चाहिए, कपड़े धोने के लिए भी बिजली चाहिए और यहां तक कि हमारे नाई भाईयों को भी लोगों की दाढ़ी बनाने की मशीन के लिए बिजली चाहिए यानि आज बिजली जीवन का एक प्रमुख हिस्सा बन गयी है। उपाध्यक्ष महोदय, बिजली के लिए लगातार आन्दोलन होते रहे हैं। चौधरी भजन लाल जी के राज में कादमा में बिजली के लिए ही लोग मारे गए, टोहाना में मारे गए और निसिंग में मारे गए। किसानों को बिजली केवल यह सरकार ही दे सकती है। जिसने इस प्रदेश का निर्माण किया है उसने ही आज बिजली का उत्पादन करने की तरफ ध्यान दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, आज हरियाणा में 1100 मैगावाट बिजली की जरूरत है। इस सरकार ने जिस आर्थिक संकट में हरियाणा में सत्ता की बागडोर संभाली, उसके बारे में तब ये मित्र कहा करते थे कि यह सरकार तीन महीने भी नहीं चलेगी और ये अपने कर्मचारियों को वेतन तक नहीं दे सकेंगे। ऐसे आर्थिक संकट में भी यदि हमारी इस सरकार के मुखिया ने 1500 मैगावाट बिजली ज्यादा पैदा करने का काम आरंभ कर दिया हो तो उसकी प्रशंसा क्यों न की जाए ? इन्होंने पूरे हरियाणा में बवंडर मचाया, परन्तु हरियाणा के गांवों के लोग इनको बैठाने तक को तैयार नहीं हैं।मंडल कमीशन के समय की बर्बादी को इन्होंने फिर से ताजा करने का प्रयास किया है। सत्ता की ललक को जिंदा रखने के लिए चौटाला साहब और भजन लाल जी ने मिलकर कोई न कोई आन्दोलन खड़ा करने की कोशिश की है। पहले इन्होंने सफाई कर्मचारियों को भड़काया और उसके बाद किसानों को परेशान करने के लिए इन्होंने शुगर मिल के कर्मचारियों को भड़काया लेकिन ये उसमें सफल नहीं हुए। इसके बाद इन्होंने बाढ़डा में, जहां पर 15 लोग मारे गए, किसानों को भड़काया। इनकी पार्टी के रहे एक उम्मीदवार ने कहा कि अब हरियाणा में कोई और पंगा खड़ा करना चाहिए, इसलिए उन्होंने राजस्थान की सीमा पर जाकर लोगों को भड़काया। यह वह जगह है जहां पर शराब की तस्करी होती है। उपाध्यक्ष महोदय, मरने वाले लोगों के साथ पूरी सरकार की, चौधरी बंसीलाल की और हमारी भी हमदर्दी है। उन्होंने सोचा कि वे उसको

[श्री राम बिलास शर्मा]

चुनाव का मुद्दा बना लेंगे, क्योंकि चौटाला साहब का बेटा चुनाव लड़ने वाला था। उपाध्यक्ष महोदय, जब हम फैक्ट्स का जिक्र करें, जब तर्क की बात करें, अपनी सरकार की 18 महीने की उपलब्धियों की बात करें तब ये कहते हैं कि 16 फरवरी को बताएंगे। इनको तो भूत सवार है 16 फरवरी का। बार-बार हरियाणा की जनता ने इनकी बात को नहीं माना इसलिए हरियाणा की जनता के साथ ये धक्का करना चाहते हैं। अब 16 फरवरी की बात तो मैं कह चुका हूं। फिर इन्होंने कई बार प्रधानमंत्री बनाए। कभी कृपा राम पूनिया को, कभी चांद राम को और कभी जी०डी० तपासे को। अब कांशीराम को खड़ा करके ले आए थे, लेकिन उन्होंने कह दिया कि मैं यहां से चुनाव नहीं लड़ूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, चुनाव में कोई संविधान हो, कोई निशान हो ।(विघ्न)

श्री धर्मवीर गाबा : राम बिलास जी, आप कुछ तो सच बोलें, तब तो हम यहां बैठे। आप कभी कादमा की बात करते हैं, कभी कहीं की बात करते हैं लेकिन आपने सतनाली की बात नहीं की क्योंकि उससे आपको धक्का लगता है। सारी विधानसभा कहती रही लेकिन आपने उनके लिए हमदर्दी में दो शब्द भी नहीं कहे।

श्री रामबिलास शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कहा है कि माण्डीवाली में जो किसान मरे उनके बारे में 8 तारीख को जो लोहारू में जन सभा हुई, उसमें मुख्यमंत्री जी ने कहा कि किसानों के मरने का हमें बड़ा दुख है। यह बड़े अफसोस की बात है, यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है व हमें उनसे हमदर्दी है। जो एक सच्चाई है, उसको क्यों न बताएं ?चार लोगों को किसने प्रोवोक किया था ? कादमा की बात इसलिए की गई है कि वहां बिजली आंदोलन चल रहा था। उपाध्यक्ष महोदय, उन्हें लोगों ने जाकर आंदोलन की जगह दी। आंदोलन की जगह होती है एस०डी०एम० का दफ्तर। अगर कोई जन-आंदोलन हो तो गांव की चौपाल। लेकिन उन्होंने राजस्थान की सीमा पर माण्डीवाली में आंदोलन किया। उस इलाके में मैं आज भी रहता हूं। इनके जलाने से भी मेरा घौंसला नहीं जला। जो व्यक्तिगत बात है, वैसे मैं उसकी चर्चा यहां पर नहीं करना चाहता। वहां पर किसान नहीं बैठना चाहते थे। बड़ जंगल है, दोनों तरफ उसमें पहाड़ियां हैं। धर्मवीर गाबा जी वहां गए थे। वे जानते हैं कि उसकी लोकेशन कहां है। मैंने खुद उन खेतों में पशु चराए हैं। मंडोला गांव से मंडीवाली 8 किलोमीटर के रेडियस पर है, वहां नावां खिचरौता के सेठ गांव में प्याऊ लगवाने इसलिए जाया करते थे कि हाली पाली को पानी मिले वहां उनको मोर्चाबंदी के लिए कौन ले गया था ये तो उपाध्यक्ष महोदय, आप देखना। उपाध्यक्ष महोदय, विपक्ष के लोग सरकार की प्रशंसा नहीं सुन सकते। उपाध्यक्ष महोदय, देश के वर्तमान प्रधानमंत्री ने फरीदाबाद में 410 मेगावाट के गैस पर आधारित प्लांट का जब उद्घाटन किया तो उस समय उन्होंने कहा कि बंसी लाल का दूसरा नाम विकास है और यह भी कहा कि पूरे हिंदुस्तान में हम गैस पर आधारित प्लांट हरियाणा को देना चाहते हैं। इस पर 1200 करोड़ रुपया केन्द्र सरकार खर्च करेगी, जिससे पैदा होने वाली बिजली हरियाणा के किसानों और मजदूरों को मिलेगी। उपाध्यक्ष महोदय, इससे बड़ी उपलब्धि और क्या होगी कि विपक्ष के भाई हमारी सरकार के 19 महीनों के शासनकाल के दौरान विधान सभा के अन्दर और बाहर एक भी बात हमारी सरकार के खिलाफ स्थापित नहीं कर सके हैं। यह बात हम डंके की चोट के साथ कह सकते हैं। हमने शिक्षा जगत में और हर क्षेत्र में विकास के कार्यों को चार कदम आगे बढ़ाया है, जबकि दिल्ली का मौसम हमारे प्रतिकूल था। अब तो वह दिन भी आने वाला है, जब दिल्ली में राम राज्य स्थापित होगा और घर की वही का खाता रखने वाला अटल बिहारी वाजपेयी होगा उस दिन हमारी सरकार की विकास करने की रफ्तार और तेज हो जायेगी। इन 19 महीनों में जो हमारी सरकार ने विकास किया है, यह तो चौधरी

बंसी लाल जी ने बन्धे हुए हाथों से किया है। विपक्ष के मित्र तो देश में मौसम बदलने से चिंतित हैं, इसलिए उनकी न तो विधानसभा की कार्यवाही में रुचि है और न ही हरियाणा के लोगों के दुख-तकलीफों को सुनने में। क्योंकि उनके पास चुनाव लड़ने के लिए कोई उम्मीदवार नहीं है। लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि "बासी चाय किटली में-कांग्रेस गई इटली में"। उपाध्यक्ष महोदय, आज हम देश की आजादी की 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। आज से पच्चास साल पहले माँ भारती के बेटों ने फांसी के फंदे में फंस कर देश को आजादी दिलाई थी। आज हम उन सपूतों को नमन कर रहे हैं। न केवल हम उनको नमन कर रहे हैं, बल्कि उनके प्रति हम कृतज्ञ हैं, जिन्होंने पहले तो इतने समय तक देश में अंग्रेजों की गुलामी बर्दाश्त की और फिर हजारों कुर्बानियां दीं। अब ये विपक्षी भाई 50वीं वर्षगांठ को भूलकर देश की इज्जत और भावना पर शासन करना चाहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जब इनकी भ्रष्टाचार की नाव इतनी भर गई कि वह डूबने लगी तो इन्होंने कहा कि बहन जी हमारी नाव डूब रही है, इसको पार लगाओ। ये सदन में रहें या न रहें, इस बात का कोई महत्व नहीं है क्योंकि इस देश के गावों में गरीबों की 36 बिरादरियां रहती हैं और प्रजातंत्र को चलाने की जिम्मेबारी सारी जनता की है। ये विपक्षी भाई तो आने वाली चिन्ताजनक घड़ियों से चिन्तित हैं। अब विपक्षी मित्र चले गये, क्योंकि उनके पास बोलने के लिए तो कोई मुद्दा था नहीं। इससे पहले भी इन्होंने कोई ऐसा मुद्दा नहीं उठाया। चौटाला साहब एक घंटे 55 मिनट बोले, लेकिन कुछ भी नहीं कह सके–सिवाय तीन-चार कहानियों के। उपाध्यक्ष महोदय, जितने भी साथियों ने अच्छे सुझाव दिये, चाहे वह शिक्षा के बारे में हो या दूसरे क्षेत्र के बारे में हो हमने उन पर मुश्तैदी से अमल किया है। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता था। धन्यवाद।

मुख्यमंत्री (श्री बंसी लाल) : उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में मेरे ख्याल से राज्यपाल महोदय, के अभिभाषण पर इतनी लम्बी चर्चा शायद पहले कभी नहीं हुई होगी, जितनी इस बार हुई है। यहां पर बहुत सी बातें हमारे विरोधी साथियों ने कही। मैं बार-बार यह कहता था कि ये जवाब सुनने के लिए यहां पर उपस्थित नहीं रहेंगे। श्री ओम प्रकाश चौटाला जी चले गए। जब चौधरी भजन लाल जी जाने लगे तो मैंने उनसे पूछा कि आप कहां जा रहे हो तो वे कहने लगे कि मैं दिल्ली जा रहा हूं। मैंने उनसे पूछा कि दिल्ली आप क्या करेंगे, हाउस तो यहां पर चल रहा है ? इस पर उन्होंने कहा कि वहां पर मेरी मीटिंग है। मैंने रात को इस बारे में पता किया कि मीटिंग कहां पर है। कांग्रेस पार्टी के बहुत से भाईयों के साथ मेरी दोस्ती है, क्योंकि उम्र भर मैं कांग्रेसी रहा हूं। पता करने पर मालूम हुआ कि आज तो वहां पर कोई मीटिंग नहीं है तथा इस प्रकार चौधरी भजन लाल जी बहाना बना कर के चले गए। चौधरी धीरपाल जी को मैंने कल भी कहा, आज भी कहा और उनको लॉबी में जाकर के भी मैं कहकर आया कि आप सदन में आ जाएं। इस पर चौधरी धीरपाल जी ने मुझे से कहा कि यदि डॉ० बीरेन्द्र पाल को सदन में बुला लोगे तो हम भी सदन में आ जाएंगे। मैंने उनसे कहा कि मैं इस बारे में स्पीकर साहब से प्रार्थना कर लेता हूं। मैंने स्पीकर साहब से जब इस बारे में प्रार्थना की तो इसके लिए वे मान गए। उपाध्यक्ष महोदय, उसके बाद आपके स्टॉफ का आदमी जब उनके पास गया, तब चौधरी धीरपाल जी ने कहा कि उनके साथी नीचे गए हैं, मैं उनको लेकर के सदन में आता हूं। लेकिन अभी तक तो वे सदन में आए नहीं हैं। फिर भी हम उम्मीद रखते हैं कि वे यहां पर आ जाएंगे। सबसे ज्यादा चर्चा हमारे विरोधी भाईयों ने यहां पर जो की तथा जिसकी चर्चा वे जनता के बीच में जाकर के भी करते रहे हैं वह यह है कि हविपा-भाजपा की गठबंधन सरकार ने चुनावों से पूर्व किए हुए वायदे पूरे नहीं किए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी सेवा में अर्ज करना चाहता हूं कि हम ने कई वायदे पूरे किये हैं और एक-एक कर के मैं गिनवाता भी हूं कि हम ने जनता के बीच में जाकर क्या क्या वायदे किए हैं। चाहे भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया वायदा हो अथवा हरियाणा विकास पार्टी द्वारा किया गया वायदा हो। आने वाले अगले साढ़े तीन वर्षों में

[श्री बंसी लाल]

हम एक-एक वायदा पूरा कर देंगे तथा मैं विश्वास दिलाता हूं कि कोई भी वायदा पूर्ण किया जाना बाकी नहीं रहेगा। (थंपिंग) जो मैनीफैस्टो चुनावों के दौरान बनाया जाता है, वह पूरे पांच वर्ष के लिए तैयार किया जाता है लेकिन अभी तो हमें जुम्मा-जुम्मा डेढ़ साल ही हुआ है। ये भाई 18 साल यहां बैठे रहे हैं, ये बताएं कि ये क्या करके गए हैं? श्री ओम प्रकाश चौटाला जी ने कहा कि उनके राज में बिजली सस्ती थी और आज पौने चार रुपये प्रति यूनिट डोमैस्टिक-पॉवर सप्लाई की जा रही है। मैं इसका भी जवाब दे दूंगा। एक श्री ओम प्रकाश चौटाला जी ने कहा कि उनके राज में बिजली 12 रुपये प्रति हार्स पॉवर दी जाती थी। मैं इसका भी जवाब दे दूंगा कि उस समय बिजली क्या भाव थी? उन्होंने तो यहां तक कहा है कि उनके राज में बिजली बहुत ही सस्ती थी तथा किसानों को रियायत देने वाले सिर्फ वे ही एकमात्र मुख्यमंत्री थे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिए सदन को बताना चाहता हूं कि महेन्द्रगढ़, बाढड़ा और दादरी के कुछ इलाकों में जो रियायत दी गई थी, वह 1971 में मैंने दी थी। उस वक्त तो ये सरकार के आस-पास भी नहीं थे। **(इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए)** श्री ओम प्रकाश चौटाला व चौधरी भजनलाल जी ने कहा कि बंसी लाल जब कादमा में गए थे तो उन्होंने लोगों को यह कहा था कि तुम्हारे बिजली के बिल माफ कर दिए जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस समय मेरे साथ भाई नृपेन्द्र जी थे, डॉ० धर्मवीर यादव थे तथा और भी बहुत से अन्य साथी थे, जब हम वहां पर गए। आपको तो याद होगा कि कादमा जाने का रास्ता कितना खराब था, पेड़ काट-काटकर पेड़ों के ढेर सड़कों पर लगा रखे थे। परिणामस्वरूप हम महेन्द्रगढ़ की सड़क पर गए और महेन्द्रगढ़ जिले के गांव आकोदा के कच्चे रास्ते से वहां पर पहुंचे। हमें अपनी गाड़ियों को खेतों में से चलाना पड़ा तथा सड़कों पर से दरख्त हटवाने पड़े तब जाकर के हम अपने गंतव्य पर पहुंचे। जब हम कादमा में पहुंचे तो उस समय वहां पर एक आदमी का दाह-संस्कार हो रहा था, हम भी उस में शामिल हुए। इससे करीब चार घंटे पहले चौधरी देवी लाल जी वहां पर आकर के चले गए थे और वहां पर वे एक ही बात कह कर के गए थे कि हमें मौजूदा सरकार को हटाना है। उनकी मरने वालों के साथ कोई हमदर्दी नहीं थी। इसी प्रकार मंडियाली गांव में मीटिंग हुई, वहां भी उन्होंने यही बात कही कि इस सरकार को हटाना है। इसके बाद धनाथी पहुंचे। वहां पाल-पाल पर आदमी बैठे हुए थे। उस समय चौधरी अतर सिंह भी जिन्दा थे, वह वहां पर हम से पहले ही आ गए थे। एक व्यक्ति ने हमें कहा कि चौधरी कुछ भी हो जाए लेकिन हम बिल नहीं भरेंगे, इस पर मैंने कहा कि मैं तो आपको बिल नहीं भरने की राय नहीं दूंगा। मैंने पाल-पाल पर बैठे सभी लोगों को ऐसी राय दी कि बिल तो आपको भरने ही पड़ेंगे। दूसरी तरफ ये भाई तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि उनके पास ही ये खड़े थे। अध्यक्ष महोदय, श्री ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि मैंने दादरी रैस्ट हाउस में किसानों से बात की। मैंने रैस्ट हाउस में किसानों को बुलाया और उनसे तफसील से बात की और वे किसान मेरे से हां करवा कर चले गए मगर बाहर जाते ही ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी के कंडीडेट रविन्द्र सांगवान ने 2-3 दिन के अन्दर ही उनको फिर भड़का दिया। यह जहां झगड़ा हुआ अध्यक्ष महोदय, जैसा रामविलास जी ने बताया कि इन लोगों ने वह जगह तलाश की जहां राजस्थान से शराब आ सकती थी। इनके नेता शराब लाने वाले थे और शराब का धंधा करने वाले थे। जिनके ऊपर शराब के 25-25 मुकद्में चल रहे हैं। चौटाला साहब एक बात को भूल गए हैं और राम विलास ने भी बताया है कि महम में इन्होंने क्या किया सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज श्री सेतिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि "महम के उप-चुनाव में लड़ रहे प्रत्येक उम्मीदवार को केवल एक ही निजी सुरक्षा गार्ड दिया और वह भी केवल 15 मई 1990 को दिया गया था जबकि मतदान का दिन 26 मई 1990 तय किया गया था। दड़वा कलां के प्रत्येक उम्मीदवार के लिए निजी सुरक्षागार्डों की संख्या 15

बताई गई। यदि कोई व्यक्ति चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति को खत्म करना चाहता है तो यह सरल था। इस भेदभाव का कोई विशेष कारण आयोग के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। श्री अमीर सिंह के लिए लगाया गया निजी सुरक्षा गार्ड 15 मई को ही उनके पास गया था। उस दुर्भाग्यपूर्ण रात में श्री अमीर सिंह को अकेले छोड़कर जाने का उसका दिया गया स्पष्टीकरण पूर्णतया विश्वसनीय नहीं था। उस दुर्भाग्यपूर्ण रात को अमीर सिंह को कैनाल रैस्ट हाउस, रोहतक में लगभग पौने 12 बजे अजय चौटाला जो कि श्री ओम प्रकाश चौटाला का लड़का है, के साथ देखा गया था। इसका साक्ष्य है कि 11.30 बजे अमीर सिंह ने शेरसिंह जो कि उसका गनमैन था, को कहा क्योंकि अमीर सिंह को रात को कहीं जाना था जहां शेरसिंह को नहीं ले जाया जा सकता। इसके पश्चात शेरसिंह अमीर सिंह को छोड़कर कैनाल रैस्ट हाउस, रोहतक से चला गया''। कमीशन की फाईंडिंग क्या है कमीशन की फाइंडिंग ये है ''अतः आयोग ने तर्कसंगत निष्कर्ष निकाला कि श्री चौटाला और उसके आदमियों की कार्यवाहियों और आस-पास की स्थिति के फलस्वरूप ही इस दुर्भाग्यपूर्ण रात में श्री अमीर सिंह की मृत्यु हुई थी''। वह क्या बात करेंगे जिनके हाथ खून से रंगे हों। अध्यक्ष महोदय, जब तक श्री ओम प्रकाश चौटाला इनकी पार्टी इनके पिताश्री हरियाणा प्रदेश की राजनीति पर हावी नहीं हुए उस वक्त तक इस हरियाणा प्रदेश में अमन चैन था। किसी किस्म का कोई लड़ाई झगड़ा प्रदेश में नहीं था। हम इलैक्शन लड़ते थे हमारे साथ एक ड्राइवर होता था इसी तरह से दूसरे कैंडीडेट के साथ एक ड्राइवर होता था हम इक्ट्ठे बैठ कर किसी ढाबे या किसी रैस्टोरां पर चाय पी लेते थे सबके चाय के पैसे एक ही कैंडीडेट दे देता था और अलग अलग चले जाते थे लेकिन चौधरी देवी लाल और श्री ओम प्रकाश चौटाला के आने के बाद हरियाणा प्रदेश के हालात ऐसे हो गए जैसे टैरोरिस्टस से होते हैं, उससे भी ज्यादा खराब हो गए। यह तो हमारी खुशकिस्मती है कि श्री ओम प्रकाश चौटाला की मुख्य मंत्री पद से जल्दी छुट्टी हो गई। अगर वे एक साल और प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रह जाते तो हम जितने विरोधी हैं चाहे वे बी०जे०पी० के हैं, चाहे हरियाणा विकास पार्टी के हैं और चाहे कांग्रेस के हैं इनमें से कोई जिन्दा नहीं मिलता सबका सफाया कर देता। आपने देखा होगा वह सदन में कहता है कि मुझे दो मिनट दे दो सबका सफाया कर दूंगा सबका सत्यानाश कर दूंगा। अध्यक्ष महोदय, उसको सिवाय सत्यानाश के और कुछ आता ही नहीं है आप इस बात को नोट करेंगे। अध्यक्ष महोदय, किसानों पर गोलियां चलाने का हमारा कोई इरादा नहीं था। हमारी तरफ से अथोरिटीज को सख्त हिदायतें दी गई थी कि किसी को कोई गोली न लगे। अध्यक्ष महोदय, वहां मौके पर श्री ओम प्रकाश चौटाला ने किसानों को भड़का रखा था। अजय चौटाला बार बार वहां जाता था। ओम प्रकाश चौटाला कभी पांच किलोमीटर इधर कभी पांच किलोमीटर उधर लोगों को बुला बुला कर टोरचर करता था। जब पुलिस मौके पर गई तो लोग पहाड़ पर चढ़ गए। जहां पुलिस गई नीचे रेलवे लाईन ऊपर पहाड़ जब लोगों ने रेलवे लाईन बंद कर दी तब पुलिस मौके पर गई। जहां पर उन लोगों ने रेलवे लाईन बंद की हुई थी उसके आस पास कोई गांव नहीं है। ये कहते हैं कि पुलिस वाले गांव के घरों में बड़ गए, डाका डाला, लोगों का कुछ छीन लिया, औरतों की बेइज्जती की, गांव तो वहां था ही नहीं तो फिर ये किसके घरों में घुस गए। अध्यक्ष महोदय, पुलिस ने गोलियां तब चलाई जब सामने से गोलियां आने लगीं, भीड़ में से गोलियां आने लगीं। पुलिस वाले भागते हुए वहां से कुछ 12 बोर के कारतूस उठा कर लाए। वहां पर उन्होंने चारों तरफ से मोर्चाबंदी कर रखी थी। उन्होंने पुलिस वालों को एक तरफ से घेर लिया दूसरी तरफ से घेर लिया तीसरी तरफ से घेर लिया चौथी तरफ से जाने का रास्ता था उस रास्ते पर गढ्ढे खोद कर उनके ऊपर पत्थर लगा कर उनके ऊपर भिंटके लगा रखे थे ताकि कोई भाग न पाए। जब पुलिस वालों को वहां से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आया तो उन्होंने पहले टीयर गैर का इस्तेमाल किया। फिर हवाई फायर किए उसके बाद रबड़ की गोलियां चलाई। जब वे लोग किसी तरह से नहीं माने तो पुलिस वालों ने सोचा कि

[श्री दंसी लाल]

तुम मरोगे तो अध्यक्ष महोदय, जब किसी की जान पर आ बनती है तो कौन किसका हुक्म मानता है पहले वह जान बचाएगा बाद में और काम करेगा। उन हालात में पुलिस वाले क्या करते। पिछले सैशन में चौधरी भजन लाल ने कहा था कि 12 आदमी शराब पी कर मर गए जब उनसे उनके नाम मांगे तो वे उनके नाम नहीं बता सके। वहां चार आदमी शराब के कारण मरे थे। एक मरा कालेखां में और एक मरा ईगला में। अध्यक्ष महोदय, किसी जगह पर पुलिस ने कोई गोली नहीं चलाई। वहां पर चौटाला और चौधरी देवी लाल ने लोगों का झगड़ा करवाया। अध्यक्ष महोदय, मैं अब आपको मंडल कमीशन के बारे में बताना चाहूंगा। बैकवर्ड क्लास के भाईयों के लिए मंडल कमीशन ने साढ़े 27 परसैंट आरक्षण देने के लिए रिकमैंडेशन की थी। जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई उस समय हरियाणा प्रदेश में ओम प्रकाश चौटाला और देवी लाल जी की सरकारें थी उस समय उस सरकार ने दरख्त कटवा कटवा कर दिल्ली बार्डर से ले कर हरियाणा बार्डर तक सड़कों पर डाल दिए और सारे रास्ते बंद कर दिए। हर रास्ता बंद कर दिया। प्रदेश के लाखों पेड़ कटवा दिए रेलवे स्टेशन जला दिए। कुरूक्षेत्र का टेलीफोन एक्चेंज जला दिया। सोनीपत का 80-90 बसों का डिपो जला दिया जगह जगह पर सरकार की बसें जला दीं। जगह जगह सरकारी गाड़ियां जला दी। सरकार की ईमारतों को आग लगा दी। मेरे कहने का मतलब है कि 12.00 बजे सरकार भी इन्हीं की और यही आग लगाने वाले। और वही काम अब किया है। उनकी जड़ में ऐसे काम करवाने वाला वही आदमी है जो उस वक्त यानि मंडल कमीशन के वक्त था, आज भी है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार किसी जगह गोली चलवाने का कोई मौका नहीं देती हैं। यहां पर गोली तब चलाई गई जब गोली चलाने पर मजबूर कर दिया। कालेखां में जो आदमी मरा वह हमारी पुलिस की गोली से नहीं मरा बल्कि सी०आर०पी० की गोली से मरा है यह उन्होंने ओन भी किया है। अध्यक्ष महोदय, रेल की पटरियाँ उखाड़ दी गईं। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि उचाना में रेल के एक डिब्बे के अन्दर 75 आदमी बैठे थे, उसमें इनके लोगों ने आग लगा दी। बैठे हुए लोगों ने बड़ी मुश्किल से भाग कर अपनी जान बचाई। मेरे कहने का मतलब यह है कि मंडल कमीशन के नाम पर इन्होंने जो उस वक्त किया था वही अब करने की कोशिश की। ओम प्रकाश चौटाला कह रहे थे कि हमारे वक्त में 24 घंटे बिजली मिलती थी। स्पीकर साहब, उस वक्त भी 24 घंटे नहीं 7-8 घंटे बिजली मिलती थी। किसानों को जो यह बिजली 7-8 घंटे मिलती थी वह भी इसलिए मिलती थी कि जब मैं 86-87 में छः महीने के लिए मुख्यमंत्री रहा था तो उस वक्त बिजली की हालत ठीक कर गया था। उस वक्त भी डोमैस्टिक इण्डस्ट्रीज और कमर्शियल अदायरों पर कट था। अध्यक्ष महोदय, हमने कौन सी बिजली कम दी है, पूरी दी है। अध्यक्ष महोदय, पिछले साल सरसों की फसल पकने का समय आया तो उस वक्त क्या हुआ कि समय पर बारिश नहीं हुई। तब रामविलास शर्मा, धर्मवीर, नरवीर सिंह, जसवंत सिंह, बावल वाले यानि अहिरवाल क्षेत्र के साथी मुझ से मिले और भिवानी वाले भी मिले और कहने लगे कि बारिश नहीं हुई है और बिजली की कमी है। यदि सरसों की फसल को पानी नहीं मिला तो सरसों सूख जायेगी। मैंने उस वक्त सरसों की फसल के लिए इण्डस्ट्रीज बंद करवा दी और इण्डस्ट्रीज पर हफ्ते में 3-4 दिन का कट लगवा दिया और जो फैक्टरी एक मैगावाट से ऊपर की बिजली इस्तेमाल करती थी उनको तो 17 दिन या 19 दिन तक बिजली बिल्कुल दी ही नहीं, वे बंद रखी। इस तरह हमने उस वक्त सरसों की फसल को पकवाया और पिछले साल सरसों की फसल पहले सालों की अपेक्षा सबसे ज्यादा हुई। इसके बाद जब गेहूं की फसल का पकने का वक्त आया तो उस गेहूं की फसल को पकवाया। उस वक्त भी बारिश नहीं हुई थी फिर भी हमने गेहूं की फसल को पकवाया चाहे इसके लिए हमने कहीं पर भी कट लगाया। अध्यक्ष महोदय, आज मैं फिर कहता हूं कि बारिश भगवान कर दे तो अच्छी बात है अगर बारिश न आयी तो

हम किसान की सरसों और गेहूं की फसल को बिजली की कमी की वजह से फेल नहीं होने देंगे, उसको पकवायेंगे। अध्यक्ष महोदय, इन भाईयों ने क्या किया क्या नहीं किया वह मैं बताता हूं। आज हरियाणा प्रदेश को बने हुए 31 साल हो गये हैं। इन 31 सालों में हमारी कैपेसिटी, हमारी क्षमता अब तक 863 मैगावाट बिजली को जनरेट करने की है। मैं कहने जा रहा हूं कि हमारे डेढ़ साल पीछे के समय को और आगे आने वाले दो साल का समय शामिल कर लेंगे तो यानि आने वाले कुल साढ़े तीन साल में हम 1180 मैगावाट नई बिजली पैदा करके अपनी मौजूदा बिजली में शामिल कर देंगे। आप देखिए 31 साल में 863 मैगावाट और साढ़े तीन साल में 1180 मैगावाट यानि 2000 मैगावाट की बिजली हम पैदा कर पायेंगे। यदि भगवान ने चाहा तो हम इससे भी अधिक बिजली पैदा करने की कोशिश करेंगे। दो साल के बाद हमारे यहां पर कोई कट नहीं रहेगा और 3 साल बाद तो हम अपनी बिजली दूसरे प्रदेशों को बेचेंगे। अध्यक्ष महोदय, इनको यह बात अखरती है, इनको सचाई का पता है ये बार-बार यही बात कहते हैं कि चौधरी साहब दो साल के बाद जब बिजली 24 घंटे आ जाएगी तो हम किस बात पर बोलेंगे और लोगों से क्या कहेंगे और क्या कह कर लोगों से वोट मांगेगे। पानीपत में 215 मैगावाट के छठे यूनिट के बारे में चौटाला साहब और भजन लाल जी भी कह रहे थे। चौटाला साहब कह रहे थे पानीपत के छठे यूनिट के लिए चौधरी देवी लाल ने मशीनरी मंगवाई थी। अध्यक्ष महोदय, जो मशीनरी मंगवाई गई थी वह 75 या 80 करोड़ रुपये की थी और भेल उस मशीनरी का 190 करोड़ ब्याज मांग रहा है। हम उनसे बातचीत कर रहे हैं और समझौता करने में लगे हुए हैं कि हमारा जो ब्याज है उसे घटाया जाए। हमें उम्मीद है कि वे ब्याज घटा देंगे। अध्यक्ष महोदय, इस तरह की जो बातें ये लोग कहते हैं उनको महसूस नहीं होता कि ये बेमानी बात कर रहे हैं। इनको बात करने का तरीका आना चाहिए और सोच समझ कर कोई बात इन लोगों को कहनी चाहिए। ये कहते हैं कि चौधरी देवी लाल ने मशीनरी मंगवा ली थी। अगर यह यूनिट उस समय लग जाता तो 250करोड़ रुपये की लागत इसकी बनती थी अगर 1992-93 या 94 में भी चौधरी भजन लाल की सरकार के समय में यह यूनिट लग जाता तो इसकी लागत करीब 400 करोड़ रुपये आती और अब यह यूनिट 750 या 780 करोड़ रुपये की लागत से बन पाएगा। इस यूनिट को चालू करने के लिए काम चालू कर दिया गया है। पंजाब नैशनल बैंक और पावर फाईनेंस कारपोरेशन से इस यूनिट पर खर्च आने वाले पैसे का प्रबन्ध कर लिया गया है और काम अलॉट कर दिया है। हम इस यूनिट को बना रहे हैं। ये हम को कहते हैं कि बिजली नहीं आती है। हम इनसे एक बात जानना चाहते हैं कि बिजली पैदा करने के बारे में क्या इन्होंने कभी सोचा। पिछले सालों में अपनी सरकार के समय में इन्होंने कोई बिजली का यूनिट पैदा किया। बिजली जैनरेट करने के लिए इन्होंने एक भी पॉवर हाउस लगाया हो, एक भी मैगावाट बिजली पैदा करने का कोई यूनिट इन्होंने चालू किया हो तो बता दें। अध्यक्ष महोदय, 1967 में हरियाणा प्रदेश में बिजली की पर कैपिटा कन्जम्पशन 57 यूनिट थी लेकिन आज हरियाणा प्रदेश में 462 यूनिट पर कैपिटा बिजली की कन्जम्पशन है। आज हम जो यूनिट चालू करने जा रहे हैं उससे बिजली का पूरा प्रबन्ध हो जाएगा। 410 मैगावाट का यूनिट एन०टी०पी०सी० का फरीदाबाद में है और चार यूनिट और चालू होंगे। कल श्री सुरजेवाला जी कह रहे थे कि 32 मैगावाट पैदा करने के लिए इतना ज्यादा खर्च होने से उत्पादन बहुत महंगा होगा। मैं यह कहता हूं कि 32 मैगावाट बिजली हम को फालतू मिलेगी। सुर्जेवाला जी कुछ पढ़ते-लिखते तो हैं नहीं काला कोट पहन कर असैम्बली में जरूर आते हैं। अध्यक्ष महोदय, 4 प्लांट्स का जो काम एलॉट किया गया है जिसका कि काम वे चालू कर रहे हैं उसकी ड्राईंग्ज वगैरा बन कर तैयार हो गई हैं और एक-डेढ़ साल में ये सभी यूनिट्स चालू हो जाएंगे। ए०बी०बी० कम्पनी जिसको कि बिजली का ठेका दिया है उनसे 110-110 मैगावाट के चार यूनिट्स का ठेका हुआ था लेकिन हमने उनको 118-118 मैगावाट का कर दिया है इस

[श्री बंसी लाल]

प्रकार 32 मैगावाट तो हम को मुफ्त बिजली मिलेगी। इस वक्त जो चार यूनिट्स चालू हैं वे भी बहुत पुराने हो गये हैं उनका प्लांट लोड फैक्टर 30 प्रतिशत है। हमने काम करने का ठेका ए०बी०बी० कम्पनी को दिया है काम उनको अलॉट किया गया है और वे इन चारों यूनिटों का ट्रायल करके हमें देंगे प्रति यूनिट जो 30 प्रतिशत प्लांट लोड फैक्टर है वह 80 प्रतिशत प्लांट लोड फैक्टर हमारा हो जाएगा। उससे हमें 927 मिलियन यूनिट तक बिजली मिलने लगेगी। जब चारों यूनिटों का काम पूरा हो जाएगा तो 3 हजार मिलियन यूनिट बिजली हमें मिलेगी और 35 प्रतिशत कोयले की कन्जम्पशन घट जाएगी। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार हम को 250 से 270 मैगावाट तक फालतू बिजली इन चार यूनिटों से मिलेगी। पानीपत का 210 मैगावाट का छठा यूनिट हम तैयार कर ही रहे हैं। कल सुर्जेवाला जी कह रहे थे कि लिक्विड फ्यूल का काम तो कांग्रेस की सरकार ने किया था। यह बात ठीक है कि लिक्विड फ्यूल का काम कांग्रेसी सरकार ने किया था मगर वह काम भागते भागते मार्च, 1996 में इन्होंने किया था और मई, 1996 में इनकी छुट्टी हो गई थी। भारत सरकार ने जो हमको फ्यूल दिया इस बारे में मैं आपको बता दूंगा। हमने उसको कामयाब कर दिया है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में क्लीयर करना चाहता हूं। हमने इसमें 3 सौ मैगावाट और जोड़े हैं और हमारा ख्याल है कि यह छः सौ, सात सौ या आठ सौ मैगावाट तक भी जा सकता है। पिछले 10 साल से किसी भी सरकार ने बिजली की मैनटैनेंस पर कुछ इन्वैस्टमैंट नहीं की है। इस सिस्टम को स्ट्रैंथन करने के लिए मई 1996 से लेकर अब तक 49 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। 15 नए सब स्टेशन बनाने के लिए 15 करोड़ 80 लाख रुपये खर्च किए हैं। 85 सब स्टेशनों का हमने आगुमैंटेशन किया है। यह हमने कहां कहां पर किया है यह मैं आपको बता देता हूं। अध्यक्ष महोदय, 220 के०वी०का 10 करोड़ की लागत से नीसिंग में, 132 के०वी० का 5 करोड़ 50 लाख की लागत से सगरा में, 132 के०वी० का 6 करोड़ की लागत से मूनक में, 132 के०वी० का 7 करोड़ की लागत से इस्माइलाबाद में, 132 के०वी० का 5 करोड़ 50 लाख की लागत से छाजपुर में सब-स्टेशन बनाए गए हैं। इसके अलावा 66 के०वी० के दो सब-स्टेशन 5 करोड़ रुपये की लागत से हथीन में और 2.50 करोड़ रुपए की लागत से चांदपुर में बनाए गए हैं। इसी प्रकार से 33 के०वी० सब-स्टेशन का आगमैंटेशन किया है। अलेबा में 1 करोड़ की लागत से, नहला में एक करोड़ की लागत से, सीवन गेट कैथल में 80 लाख की लागत से, बरसत में एक करोड़ की लागत से, एम०आई० बहादुरगढ़ 90 लाख की लागत से, मझेरा एक करोड़ की लागत से, अटेरबा में 90 लाख की लागत से और भजगांव में 90 लाख की लागत से बनाया है। अध्यक्ष महोदय, हमने जो नए सब-स्टेशन बनाए हैं इनकी 49 करोड़ की लागत बनती है। जो आगमैंटेशन की है यह 1 करोड़ 10 लाख की की है। भिवानी में 2 करोड़ की लागत से, सिरसा में 90 लाख की लागत से, नीसिंग में 65 लाख की लागत से, पेटवा का दूसरा सब-स्टेशन 3 लाख की लागत से, भिवानी में दूसरा 220 के०वी० का 3 करोड़ की लागत से, हिसार 1-ए 50 लाख की लागत से और रोहतक में 1 करोड़ 20 लाख की लागत से सब-स्टेशन बनाए गए हैं। इसी प्रकार से नीलोखेड़ी में 1 करोड़ 20 लाख, जीवन नगर में 20 लाख, उकलाना में 65 लाख, टोहाना में 90 लाख, भिवानी में 20 लाख, हांसी में 15 लाख, चीका में 75 लाख, राई में 1 करोड़ 20 लाख, कैथल में 75 लाख, कनीना खास में 90 लाख, महेन्द्रगढ़ में 1 करोड़ 10 लाख, मीरान में 75 लाख, सफीदों में 90 लाख, फतेहाबाद में 70 लाख, चन्दौली में 1 करोड़, जीन्द -यू में 80 लाख, बहादुरगढ़ में 2 करोड़ 60 लाख, सीवन में 90 लाख, थाना में 90 लाख, मधुबन में 1 करोड़ 25 लाख, समालखा में 30 लाख, भोरे में 65 लाख, ओली में 1 करोड़, और जुही में 30 लाख की लागत के हैं। इसके अलावा 16 सब-स्टेशन 66 के०वी० के और बनाए गए हैं। 32 सब-स्टेशन 33 के०वी० के बनाए हैं। अध्यक्ष महोदय,

यहां पर वर्ल्ड बैंक के प्रोजैक्ट की चर्चा चौटाला साहब, चौधरी भजन लाल और सुर्जेवाला ने की है। इनकी समझ में यह कुछ नहीं आया की ये क्या कह रहे हैं और यह है क्या। चौधरी वीरेन्द्र सिंह बैठे बैठे यह कह कर चले गए कि हमें वर्ल्ड बैंक से केवल 60 मिलियन डालर का कर्जा मंजूर हुआ है लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह कर्जा 60 मिलियन डालर का नहीं बल्कि 600 मिलियन डालर का मंजूर हुआ है और इसकी पहली इंस्टालमैन्ट 240 करोड़ रुपये हमको फरवरी में मिलेगी। इस तरह से यह आठ दस साल तक चलेगा और बीस साल में हमको रि-पे करना पड़ेगा। लेकिन अध्यक्ष महोदय, हमारा इतने से ही काम नहीं चलेगा बल्कि हमें करीब 7900 करोड़ रुपये चाहिएं और जिसके लिए हम जापान, जर्मनी और इंगलैण्ड से बात कर रहे हैं। यह 2400 करोड़ रुपये का कर्जा हमें 16-1-98 को मंजूर हुआ है and the agreement was signed by our Ambassador. This money will be spent over a period of 8-10 years. 15 नये 220 के0वी0 के सब स्टेशंज बनेंगे, 33 नये 132 के०वी० के सब स्टेशंज बनेंगे, 20 नये 66 के०वी० के सब स्टेशंज बनेंगे तथा 17 नये 33 के०वी० के सब स्टेशंज बनेंगे। इसके अलावा 70 हजार नये ट्रांसफार्मर्ज लगेंगे और 88 हजार किलोमीटर डिस्ट्रीब्यूशन लाईन चेंज की जाएंगी। इस तरह से यह काम होगा। जो पहली किश्त 240 करोड़ रुपये की आएगी उसमें 220 के0वी० के स्टेशन पाला, यमुनानगर और शाहवाद में लगेंगे तथा 500 किलोमीटर तक 11 के०वी० की लाईनें आगुमेंटेशन होंगी। इसके अलावा 33 के-वी० के सब स्टेशन भी होंगे। अध्यक्ष महोदय, पिछले साल बजट ऐलोकेशन 287 करोड़ रुपये की हुई थी लेकिन इस बार हम 325 करोड़ रुपये की बजट ऐलोकेशन करेंगे यानि पहले से इस साल ज्यादा दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, चौटाला साहब ने कहा कि सबसिडी बंद हो गयी है लेकिन हम इस साल सबसिडी सात सौ करोड़ से भी ज्यादा देने जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, अगर आप इजाजत दें तो मैं बैठकर बोल लूं क्योंकि मुझे काफी पसीना आ रहा है।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, आप बैठकर बोल सकते हैं।

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, चौटाला साहब कहते हैं कि ट्यूबवैल्ज के कनैक्शन कई सालों से नहीं दिए गए हैं इनकी यह बात ठीक है लेकिन हम नये कनैक्शन लोगों को देंगे। परन्तु इस समय यदि हम नये कनैक्शन देते हैं तो हमें उसके लिए चालीस करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्चा करना होगा और 60 मैगावाट पॉवर भी और चाहिए और हम वह कहां से लाएंगे। इसलिए हम नये कैनैक्शन दो साल के बाद ही देंगे। साथ ही बिजली बोर्ड में किसी भी ईम्पलाइज की छंटनी भी नहीं होगी और उनको पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर वेतनमान इत्यादि उसी पैटर्न पर मिलेंगे जिस पर सैंटर गवर्नमैंट ने दी हैं। अध्यक्ष महोदय, चौटाला साहब ने एक खत पढ़ दिया कि कमिश्नर, इरीगेशन ने वर्ल्ड बैंक को चिट्ठी लिखी कि बिजली के रेट ऐग्रीकल्चर के ऊपर बढ़ जाएंगे। हमारे कमिश्नर एस०वाई० कुरैशी ने 11-12-97 को वर्ल्ड बैंक को चिट्ठी लिखी है उसमें क्लीयर कट लिखा है कि ऐग्रीकल्चर के ऊपर कोई टैरिफ नहीं बढ़ेगा। वे अपने मतलब की बात पढ़ गए । चौटाला साहब कहकर गए कि वे 24 घंटे बिजली देते थे लेकिन हमारा रिकार्ड कहता है कि वह 8 घंटे बिजली देते थे। जैसी मैंने अर्ज की कि हम बिजली पर कोई टैरिफ नहीं बढ़ा रहे यह कन्सैशनल टैरिफ 1971 में मैंने दिया था 13 पैसे पर यूनिट और 51 से 100 तक 12 पैसे। 1988 में चौधरी देवी लाल ने 23 पैसे से 28 पैसे किया था और 51 से 100 तक 18 रुपये 50 पैसे से 23 रुपये इस प्रकार चौधरी देवी लाल के राज में दो बार रेट बढ़ाए गए 23 पैसे से 28 पैसे और 18 रुपये 50 पैसे से 23 रुपये पर एच०पी०। चौटाला साहब कह रहे थे कि हमारे टाईम 12 रुपये हॉर्स पॉवर के थे और दिसंबर 1990 में इन्होंने फिर रेट बढ़ाए। डौमैस्टिक बिजली

[श्री बंसी लाल]

के 50 पैसे से 40 यूनिट तक 65 पैसे और उससे ऊपर 1 रुपये 25 पैसे। इस प्रकार दो दफा रेट बढ़ाए।

अध्यक्ष महोदय, हमने करप्शन बंद करने की तरफ पूरे कदम उठाए। हमने बैकडोर से कोई भर्ती नहीं की। चौधरी भजन लाल जी और उससे पहले चौटाला जी के समय में बैकडोर भर्ती होती रही। पहले ऐड-हॉक लगा दिया और फिर रैगुलर कर दिया और कई हजार आदमी लगा दिए और डौमैस्टिक पॉवर के बिल जो 50 परसैंट भी भर देता है हम उनके ट्रांसफार्मर रिप्लेस कर देते हैं। रणदीप सुर्जेवाला कह गए कि सरकार ने इतना कर्जा लिया है कि जिसका ब्याज भी नहीं पुगेगा। अध्यक्ष महोदय, ऐसा कोई काम नहीं है वर्ल्ड बैंक ने बाकायदा सर्वे करके अप्रेजल किया। चौधरी भजन लाल जी ने यमुनानगर का जिक्र किया। उन्होंने यमुनानगर के प्लांट का फाउंडेशन स्टोन फरीदाबाद में बैठकर लगाया था लेकिन हुआ कुछ नहीं। हम ही उसको पूरा करेंगे।

बैठक का स्थगन

Mr. Speaker : Now the House is adjourned for 40 minutes.

(The Sabha then adjourned and re-assembled at 1:06 p.m.)

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)

मुख्य मंत्री (श्री बंसी लाल) : अध्यक्ष महोदय, चुनावों से पहले हम ने एक वायदा हरियाणा की जनता के साथ किया था कि हम भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे । इसकी तरफ हम ने विशेष व सख्त कदम उठाए हैं। हम ने रिश्वत लेने वाले अधिकारियों, चाहे वे कितने भी बड़े क्यों न हों, किसी को माफ नहीं किया है। अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकारों के वक्त में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार नौकरियां देने में यहां पर होता था, यहां पर सरकार के दलाल घूमते थे और कहते थे कि इतने रुपये दे दो, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। लेकिन दूसरी और आज हम ने सलैक्शन बौर्ड का नाम बदलकर सलैक्शन कमीशन कर दिया है जो कि एक इंडिपैंडेंट बॉडी है। उसका एक निर्धारित समय का टर्म होता है। अध्यक्ष महोदय, जितनी भी भर्तियां की हैं, वे मैरिट के आधार पर की हैं और कोई भी भर्ती हम ने बगैर मैरिट के नहीं की है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आज तक पूरे राज्य से कोई भी व्यक्ति यह शिकायत लेकर के हमारे पास नहीं आया है कि किसी उम्मीदवार को पैसे लेकर के भर्ती किया गया है। पिछली सरकारों के समय में क्या होता था कि नौकरियाँ देने के तीन महीने बाद ही सलैक्शन बोर्ड का रिकार्ड जला दिया जाता था। हम ने आते ही यह प्रावधान कर दिया है कि सलैक्शन कमीशन का कोई भी रिकार्ड जलाया नहीं जाएगा, और उसको बाकायदा कम्पयूटराईज्ड किया जाएगा ताकि दस साल के बाद भी जो भी सरकार प्रदेश के अंदर होगी तथा कोई भी उम्मीदवार सरकार को यह शिकायत करेगा कि उससे कम मैरिट वाला लड़का भर्ती कर लिया गया है और उसको इग्नोर कर दिया गया है तो सरकार इस स्थिति में होगी कि वह कम्प्यूटर की फ्लॉपी निकाल कर के शिकायतकर्ता को दिखा सकेगी कि जो लड़का भर्ती किया गया है, उसके इतने नम्बर हैं और शिकायतकर्ता के इतने नम्बर हैं। इस प्रकार से हमने भ्रष्टाचार को बंद कर दिया है। अध्यक्ष महोदय, हम ने ए०एस०आई० पदों की भर्ती के लिए लड़कों का फिजीकल टैस्ट लिया तथा यह टैस्ट हजारों लड़कों की उपस्थिति में लिया गया। जो भी लड़के टैस्ट में पास या फेल हुए, वे हजारों

लड़कों के सामने हुए। लेकिन पहले क्या होता था कि इस प्रकार की भर्ती में मुख्यमंत्रियों के घरों में उम्मीदवारों के कद व वजन का नाप-तौल वगैरह हो जाता था। अध्यक्ष महोदय, चुनाव आयोग ने हमें यह आदेश दिया है कि यह भर्ती चुनावों के बाद में की जाए, हम ने कहा कि ठीक है, हम चुनावों के बाद में यह भर्ती कर लेंगे। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो लड़के फिजीकल टैस्ट में पास हुए हैं, केवल उन्हीं लड़कों में से ही यह भर्ती की जाएगी तथा बाहर से दूसरे उम्मीदवारों में से नहीं की जाएगी। इसी प्रकार से पुलिस के लगभग 2 हजार कांस्टेबल और भर्ती किये जाने हैं। चुनाव आयोग ने आदेश दिया है कि यह भर्ती भी चुनावों के बाद की जाए तो हम ने भी कह दिया कि चुनावों के बाद कर लेंगे और मैंने इस बारे में खुला ऐलान भी किया है कि जब भी पुलिस की भर्ती होगी तो हर जिला मुख्यालय के मैदान में भर्ती का मेला लगाया जाएगा तथा इस भर्ती में जिन लड़कों को चुना जाएगा, वह कार्य सब के सामने होगा। हजारों लड़कों के बीच में से छांटकर बाकायदा मैरिट के आधार पर यह भर्ती की जाएगी। उसी समय सब के सामने यह भी कह दिया जाएगा कि इन लड़कों के बीच में से भर्ती के लिए ये-ये लड़के छांटे गए हैं और इस बारे में अगर किसी को कोई शिकायत हो तो वह बताए। हमने हरिजनों और बैकवर्ड भाईयों के लिए छाती में एक इंच की छूट दी है और एक इंच की कद में छूट दी है। स्वर्ण जाति के मैट्रिक पास जवान कांस्टेबल भर्ती हो सकेंगे और हरिजन तथा बैकवर्ड जवान मिडिल पास ही कांस्टेबल भर्ती होंगे। क्योंकि हमें 'ए' क्लास और 'बी' क्लास का कोटा पूरा करना होता है। अध्यक्ष महोदय, हमने रिश्वत को बन्द करने के लिए हर किस्म के कदम उठाए हैं। अगर ये विरोधी भाई और जनता हमारा साथ दे तो हम रिश्वत को एकदम खत्म कर सकते हैं। करप्शन मिटाने का वायदा हमने पूरा किया।

दूसरी तरफ हमने जनता से वायदा किया था कि शराब बन्द करेंगे। हमने शराब कानूनन सत्ता में आते ही बन्द कर दी लेकिन मैं मानता हूं चोरी छुपे जो शराब आती है जैसा कल प्रोहिबिशन मिनिस्टर श्री गणेशी लाल ने आपको कहा कि अगर 10 परसैन्ट भी आती है तो 90 परसैन्ट तो बन्द हो गई । पहले आखिरी बस में जो शहर से गांव जाती थी कोई इज्जतदार व्यक्ति उस बस में बैठ नहीं सकता था माताओं और बहनों के तो बैठने का सवाल ही नहीं उठता। आज आखिरी बस में हमारी माताएं और बहनें अकेले सफर कर सकती है, कोई रुकावट नहीं है। पहले गांव की गली में और शहर की सड़कों पर कोई शरीफ आदमी कोई इज्जतदार आदमी, माताएं और बहनें गली में या सड़क पर नहीं निकल सकते थे और आज अकेले कहीं भी घूमें कोई रुकावट नहीं है अगर कोई चोरी छुपे शराब पी भी लेता है तो पीकर घर में छुप जाता है और बाहर नहीं निकलता। पहले हर होली पर, हर दीवाली पर 10-10, 12-12, आदमी शराब पीकर झगड़ा करके मारे जाते थे। उसके बाद 2 दीवालियां आई, एक होली आई, शराब बन्द करने से कोई आदमी मरना तो दूर किसी को चोट तक भी नहीं लगी। अध्यक्ष महोदय, शराब के मामले में जितनी सख्ती हमने दिखाई है ऐसी सख्ती कोई सरकार नहीं दिखा सकती। अगर कोई यह कहे कि 100 प्रतिशत शराब बन्द कर दें तो 100 परसैन्ट का मैं कभी क्लेम नहीं करूंगा। ताजी राते हिन्द (इंडियन पीनल कोड) अंग्रेजों के जमाने में बना था और 100 साल से भी पुराना है जिसके अनुसार कत्ल करना जुर्म है, कत्ल करने की कोशिश करना भी जुर्म है, डकैती जुर्म है, रोबरी जुर्म है और रेप जुर्म है। वे आज भी होते हैं। आज अगर जनता 100 फीसदी साथ दे तो शराब भी पूरी तरह से बन्द हो जाएगी। लेकिन आज हम शराबबन्दी में बिल्कुल कामयाब है। इसी महीने के एक तारीख के अखबार में आप पढ़िए कि एक बस के कंडक्टर से किसी औरत ने टिकट मांगा। कंडक्टर ने टिकट दे दिया और पैसे ज्यादा मांग लिए। औरत ने कहा कि आप पैसे तो ज्यादा मांग रहे हैं। कंडक्टर ने कहा कि ये तो बंसी लाल ने शराब बन्द करके बढ़ा दिए हैं। कंडक्टर और ड्राईवर दोनों ही मेरी बुराइयां करने लगे। उस बस में अलग-अलग 2 जिले की 14 औरतें थीं। 14 की 14 औरतें कंडक्टर और ड्राईवर के गले

[श्री वंसी लाल]

पड़ गई। उस वक्त में एक फौजी भी बैठा हुआ था उसने कहा कि मैं इतने वर्षों से फौज में रहा हूं मैंने शराब को कभी अपने ऊपर इतना हावी नहीं होने दिया। शराब बन्द होने से माताओं बहनों को कितना आराम हुआ है। बच्चों की किताबें मिलने लग गई उनको कपड़े अच्छे मिलने लग गए उनकी पढ़ाई ठीक होने लग गई घरों में जो क्लेश होता था वह बंद हो गया। शराब बंद करने में हमें पूरी कामयाबी मिली है। यह वायदा भी हमने पूरा किया है। अध्यक्ष महोदय, बिजली का मैंने आपको बता ही दिया है कि हम दो साल के बाद किसानों को 24 घंटे बिजली देंगे यह वायदा भी हम पूरा कर रहे हैं। नहरों की सफाई हमने करवा दी। अध्यक्ष महोदय, चौधरी देवी लाल ओम प्रकाश चौटाला और चौधरी भजन लाल तो भिवानी जिले को हरियाणा प्रदेश में नहीं समझते थे वह तो उसको पाकिस्तान में समझते थे। इन्होंने भिवानी जिले में कभी भी कोई पैसा खर्च नहीं किया। हमने चौटाला के जिले में विकास के कार्यों पर खूब पैसा खर्च किया है और भजन लाल के जिले में भी काफी पैसा खर्च किया है। अध्यक्ष महोदय, महम हल्के से सजपा वालों का एम०एल०ए० है वहां के बारे में हमने यह नहीं सोचा वहां का एम०एल०ए० किस पार्टी का है वहां हमेशा पानी रुकता था उसका हमने प्रबंध कर दिया है। अकेले रोहतक जिले में दो ड्रेन्ज बनाने पर हमने 24 करोड़ रुपया खर्च किया है वह पैसा हमने महम ड्रेन और लाखनमाजरा ड्रेन बनाने पर खर्च किया है। अब हमने एक तीसरी प्लान बना रखी है उसको हम नैक्सट फाइनैंशियल ईयर में चालू करेंगे। अध्यक्ष महोदय, हम होसी, भिवानी और दादरी तक का जो ज्यादा बरसात होने से पानी खड़ा हो जाता है वह हम डालेंगे ड्रेन नम्बर 8 में और हिसार का और उधर का जितना सेम का पानी है या जो पानी ऊपर आ गया है उसको डालेंगे हम घग्गर नदी में। यह काम भी हम कर रहे हैं। नहरी पानी का वायदा भी हमने पूरा किया है। हमने किसानों को नहरी पानी पूरा दिया है। अध्यक्ष महोदय, हमने ड्रेन्ज की सफाई का काम करवा दिया है। उनमें 20-20 साल से दरखत खड़े थे हमने उनको कटवा कर उनकी सफाई करवा दी है। हमने रोहतक जिले में ड्रेन्ज की सफाई पर 18 या 20 करोड़ रुपया खर्च किया है। जींद जिले का पानी और सोनीपत जिले का पानी लाखनमाजरा ड्रेन में डालेंगे। पूरे प्रदेश में ऐसा करेंगे उससे बाढ़ रहित हरियाणा होगा। हमने यह वायदा भी पूरा किया है। अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं यह कहना चाहूंगा कि हरिजन और बैकवर्ड भाइयों के लिए सरकारी नौकरियों में जो रिजर्व कोटा था उसको किसी भी सरकार ने पूरा नहीं किया हमने उसको पूरा किया है। प्रदेश में दूसरे विकास के कार्य चालू हैं। अध्यक्ष महोदय, यह जो किसानों के एजीटेशन की बात कही जाती है यह कोई एजीटेशन नहीं है यह तो हमारे विरोधी भाईयों की हमारे खिलाफ फैलाई हुई बगावत है। जब वहां पर गोली चलने से कोई एक दो मरे तो उसके बारे में हमारे विरोधी भाई कहते हैं कि यदि वहां पर 10-5 आदमी मर जाते तो अच्छा था। हमारे विरोधी भाई लाशों पर राजनीति करना चाहते हैं। हम इनकी तरह लाशों पर राजनीति नहीं करना चाहते हम तो ईमानदारी की राजनीति करना चाहते हैं ताकि सब तरह से ठीक हो। अध्यक्ष महोदय, 1972 में असैम्बली के इलैक्शन हुए। उन इलैक्शंज में रिजक राम, प्रताप सिंह दौलता, चौधरी हरद्वारी लाल और दल सिंह ये सब हमारी विरोधी पार्टी के थे, जीत कर यहां आए। यहां आ कर उन्होंने असैम्बली की डिबेट में सबसे पहले तकरीर की कि हम चीफ मिनिस्टर को मुबारिकबाद देते हैं कि इन्होंने फ्री एंड फेयर इलैक्शन कराए। अध्यक्ष महोदय, मैं आज भी यह कहता हूं कि जो लोक सभा का इलैक्शन होने जा रहा है वह भी हम बिल्कुल फ्री एंड फेयर करवाएंगे। उसमें कोई अनफेयरनस यूज नहीं करेंगे। (थम्पिंग) हमने एक वायदा यह किया था कि हर महीने की 7 तारीख तक बुढ़ापा पैंशन दिया करेंगे। आज किसी गांव या शहर में 8 तारीख नहीं होती 7 तारीख को पैंशन दे दी जाती है। एक वायदा हमने किया था कि हम लोकपाल बिल पास करेंगे। हमने वह बिल पास कर दिया। वह राष्ट्रपति जी के यहां

मंजूरी के लिए भेजा हुआ है। जैसे ही वहां से उसकी मंजूरी आ जाएगी वह कानून बन जाएगा। हमने यह वायदा भी पूरा किया। एक वायदा हमने यह किया था कि हम 100 किलोमीटर तक के रूट परमिट एजुकेटिड अनएम्लायड यूथस की कोआपरेटिव सोसाइटीज को देंगे। अध्यक्ष महोदय, हमने तकरीबन 500 रूटस आईडेन्टीफाई कर दिये हैं और उनकी एडवर्टाईजमेंट कर दी गई है। इलैक्शन कमीशन ने कहा कि इलैक्शन के बाद इन्हें दें तो हमने कहा है, ठीक है हम इलैक्शन के बाद फाईनल कर देंगे। रूटस तो 500 हैं लेकिन परमिट कुछ ज्यादा हो गए हैं क्योंकि हर रूट पर परमिट होगा। पहले हमने 100 किलोमीटर तक रूट परमिट देने की बात कही थी लेकिन अब हम 125 किलोमीटर तक देंगे। मैं बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से सरकारी नौकरियों में क्लास-1 और क्लास-2 के लिए हरिजनों व बैकवर्ड क्लासिज के भाईयों के लिए नौकरियों में आरक्षण है उसी प्रकार से हम इन रूटस परमिट में भी रिजर्वेशन करेंगे, और यह होगा।

अध्यक्ष महोदय, आज धीरपाल जी चले गए। उनको बाहर से बुलाने के लिए दो बार मैंने भी कोशिश की। उन्होंने कहा कि वीरेन्द्रपाल जी को वापस बुला लो और उनको माफ कर दो, उस बारे मैंने आपसे बात की और आप मान भी गए थे। आपने भी अपने आदमी भेजकर उनको बुलाने की कोशिश की लेकिन वे नहीं आये क्योंकि उन्होंने भागना जो था।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं हवाई यात्रा के बारे में कहना चाहूंगा। जब से कोड ऑफ कन्डैक्ट लागू हुआ है, इलैक्शन कमीशन की तरफ से हमने किसी हवाई जहाज का इस्तेमाल नहीं किया और न ही करेंगे। इस बारे मैं बताना चाहूंगा कि चौधरी देवी लाल जी की तरह हवाई यात्रा का 33 लाख रुपये से अधिक का बकाया पड़ा है जो उन्होंने आज तक नहीं दिया है। इसी प्रकार से उनकी बजारत में रहे एक मंत्री डॉ० के०आर०पुनिया की तरफ 1 लाख से अधिक का बकाया है। इसी प्रकार से चौधरी हुक्म सिंह की तरफ और एक दूसरे उनके साथी सम्पत सिंह की तरफ 45853 रुपये बकाया पड़े हैं। ये सभी उनकी बजारत में वजीर थे। जैसे ये लोग खुद हैं वैसा ही दूसरों को समझ रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर चौधरी भजन लाल ने किसानों पर गोली चलाने की बात कही। मुझे बड़ी हैरानी हुई चौधरी भजन लाल पर कि वे कब से किसानों के हमदर्द हो गए। उनके समय में किसानों पर नीसिंग में गोली चली, वहां पर किसान मरे, इसी प्रकार से टोहाना, नारनौंद, लोहारू और कादमां में गोली चली थी जहां पर किसान मारे गए थे। मैं बताना चाहूंगा कि एक बार किसान ट्रैक्टर लेकर अपना डैमोस्ट्रेशन करने के लिए, यहां चण्डीगढ़ में जलूस निकालने के लिए आ रहे थे तो उनके ट्रैक्टरों के इंजन में मिट्टी भरवा दी थी ताकि वे यहां पर न आ सकें, अब वे किसानों के हमदर्द बनते हैं। हमने जानबूझकर किसानों पर कोई गोली नहीं चलवाई। चौधरी देवी लाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के वक्त में मण्डल कमीशन की रिपोर्ट की आड़ में उन लोगों ने स्टेशन चलाये, रेलें बंद करवाई और न जाने कितना नुक्सान करवाया था।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं एक एडीशनल सूचना बिजली के बारे में हाउस को देना चाहूंगा। वर्ष 1996 में हमारे यहां पर बिजली की अवेलेबिलिटी 312 लाख यूनिट पर डे थी जो आज वर्ष 1998 में 377 लाख पर डे हो गई है। It is higher than 33% of the present production. हमने किसानों को 700 करोड़ रुपये से ज्यादा की सबसिडी दी है और हम आगे इससे भी ज्यादा देने जा रहे हैं। चौधरी भजन लाल ने बिजली के प्राईवेटाईजेशन की बात की है कि बिजली की प्राईवेटाईजेशन इस सरकार ने कर दी है। मैं बताना चाहूंगा कि हमने बिजली की बिल्कुल भी प्राईवेटेनाईजेशन नहीं की है। मैं बताना चाहूंगा कि हम इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड की 3-4 कम्पनी बनाने जा रहे हैं। जबकि भजन लाल ने तो अपने वक्त में एक तरह से बिल्कुल ही बिजली बोर्ड की प्राईवेटाईजेशन कर दी थी। लेकिन हम अब

[श्री बंसी लाल]

3 कम्पनीज बनाने जा रहे हैं। एक पावर जैनरेट करने वाली कम्पनी होगी एक पावर ट्रांसमिशन की कम्पनी तथा एक पावर डिस्ट्रीब्यूशन की कम्पनी होगी। ये तीन कम्पनियां बिल्कुल सरकारी होंगी। ट्रांसमिशन की कम्पनी 100 प्रतिशत सरकारी होगी जो हमारी पावर जैनरेशन वाली कम्पनी होगी वह भी 100 प्रतिशत सरकारी होगी। हमारी एक कम्पनी ज्वांयट वैंचर में होगी। इन कम्पनियों के चार हिस्से बनेंगे। कम्पनियां बिल्कुल सरकारी होंगी और एक कम्पनी ज्वायंट वैंचर में होगी। अध्यक्ष महोदय, अभी हम यह एक्सपैरिमैंट करके देख रहे हैं। अगर एक्सपैरिमैंट कामयाब होगा तो इन कम्पनीज़ को आगे चलाएंगे और अगर एक्सपैरिमैंट कामयाब नहीं हुआ तो इन्हें आगे नहीं चलाएंगे। हमने किसी चीज़ को प्राईवेट नहीं किया है हमने तो मैशनेलाईज़ किया है। किसी कर्मचारी की छंटनी नहीं होगी। पांचवें वेतन आयोग द्वारा दिया गया वेतनमान भी बिजली बोर्ड के कर्मचारियों के देंगे। अध्यक्ष महोदय, किसी हिसाब से भी कर्मचारियों को कोई नुक्सान नहीं होगा। लीडरी के भूखे लोग कर्मचारियों को भड़का रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, कर्मचारी यह बात क्यों कहते हैं कि हम सरकार विरोधी हैं, उसका रीज़न भी मैं बता देता हूं। बिजली बोर्ड के तथा ट्रांसपोर्ट के कर्मचारियों के बारें में हमने कुछ आदेश जारी किए हैं जिससे उनको भारी परेशानी हुई है। मैं जिला कुरूक्षेत्र में भाषण दे रहा था। उस भाषण के दौरान मैंने यह कहा था कि बिजली बोर्ड के हर कर्मचारी को 100 यूनिट तक बिजली फ्री दी जाएगी उस वक्त उस सभा में एक बूढ़ा किसान खड़ा हो कर कहने लगा कि चौधरी साहब, मेरी बात सुनिए। मैंने उससे कहा कि कहो क्या बात है उसने कहा कि बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को 100 यूनिट से क्या होगा ये लोग तो जब सर्दी में अपनी भैंस भी नहलानी हो तो बिजली पर पानी गर्म करके नहलाते हैं। मैंने इस बारे में नोटिस लिया और यहां पर आते ही यह आदेश किया कि बिजली बोर्ड के सभी कर्मचारियों के घरों में बिजली के मीटर लगाए जाएं। इससे पहले बिजली बोर्ड के कर्मचारियों के घरों में बिजली के मीटर नहीं थे। पहले 100 यूनिट तक बिजली का बिल छोड़ दीजिए और उसके बाद जितने यूनिट कन्जथूम हो उनसे उसके पैसे लिए जाएं। तीसरे दिन ही इन कर्मचारियों ने एक मीटिंग बुलाई और यह कहने लगे कि चीफ मिनिस्टर कर्मचारी विरोधी है। इसी प्रकार से मैं रोडवेज़ की बात कहना चाहता हूं। रोडवेज़ 40 करोड़ के घाटे में चली आ रही थी। हरियाणा रोडवेज़ चौधरी भजन लाल की सरकार के समय से ही घाटे में चली आ रही है। 8-10 महीने पहले मैंने डी०सीज० को आर्डर किया था कि मैजिस्ट्रेट्स से वे बसों की चैकिंग करवाएं इससे पता चल सकेगा कि रोडवेज़ में बसों के कितने टिकट्स काटे जा रहे हैं। पहले उनको यह पॉवर नहीं थी कि वे बसों को चैक कर सकें लेकिन अब वे बसों को चैक कर सकते हैं कि बसों में कितने टिकट्स काटे जाते हैं। इस कारण रोडवेज़ के कर्मचारियों में कुछ नाराजगी की भावना है और वे कहने लगे कि मुख्य मन्त्री कर्मचारी विरोधी है जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। बिजली की स्थिति सुधारने के लिए सरकार ने जो कार्यवाही की है वह भी आपको मालूम है। मई, 1996 में इस सरकार के सत्ता में आने के बाद से 220 के०वी०ए० के 7, 132 के०वी०ए० के 4, 66 के०वी०ए० के 2 और 33 के०वी०ए० के 8 सब-स्टेशन्ज़ चालू किए गए हैं।

बैठक का समय बढ़ाना

Mr. Speaker : Is it the sense of the House that the time of the sitting be extended by 15 minutes ?

Voices : Yes.

Mr. Speaker : With the sense of the House, the time is extended by 15 minutes.

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, इसीप्रकार से 220 के०वी०ए० के 7 जगह, 132 के०वी०ए० के 25 जगह, 66 के०वी०ए० के 16 जगह और 33 के०वी०ए० के 32 जगह पर सब-स्टेशन की आगुमैंटेशन की गई है। यह लिस्ट लम्बी है अगर पूरी पढ़ूंगा तो इसमें काफी समय लग जाएगा। अध्यक्ष महोदय, फिफथ पे कमीशन के बारे में इन लोगों का एक मुगालता रहता है। ओम प्रकाश चौटाला साहब कह रहे थे कि वह वायदा पूरा नहीं किया। हम कहते हैं कि फिफथ पे कमीशन हमने अपने हिसाब से पूरा किया है लेकिन कुछ कैटेगरीज़ ऐसी हैं जो भारत सरकार में नहीं हैं लेकिन हमारे यहां हैं और कुछ कैटेगरीज़ ऐसी हैं जो भारत सरकार में हैं लेकिन हमारे यहां नहीं है। अगर उनमें कोई ऐनोमली रह गई होगी तो हमने चीफ सैक्रेटरी की चेयरमैनशिप में एक कमेटी बना रखी है वे उसमें रिप्रैजैंटेशन दे दें जो ऐनोमली होगी वह ठीक कर देंगे। हम किसी मुलाज़िम के साथ या किसी पैंशनर के साथ कोई ज्यादती नहीं करेंगे। अध्यक्ष महोदय, जिस जिस चीज की अनोमली बाकी है वह अनोमली कमेटी पूरी कर देगी। पांचवे वेतन आयोग से हमारे ऊपर साढ़े नो सौ करोड़ रुपये का एकदम वर्डन पड़ा है और हर साल पांच सौ करोड़ रुपये का वर्डन पड़ेगा।

अब एक बात इन्होंने क्राईम के बारे में कह दी थी कि आज ला एण्ड आर्डर की स्थिति खराब है। ला एंड आर्डर की स्थिति खराब पहले वाले भाई के राज में हुआ करती थी। अध्यक्ष महोदय, पड़ौसी राज्य हैं वहां पर क्राईम की स्थिति के बारे में मैं आपको बता देता हूं चण्डीगढ़ में एक लाख के पीछे 2.85 प्रतिशत मर्डर, डकैती 4.28 प्रतिशत, रौबरी 8.7 प्रतिशत, बरगलैरी 12.8 प्रतिशत और रेप 1.8 प्रतिशत है। आई०पी०सी० के अन्तर्गत 286.9 केस हुए हैं। उत्तर प्रदेश में 110.7 प्रतिशत है। दिल्ली में 57 प्रतिशत है, राजस्थान में 330.4 प्रतिशत है और हरियाणा में 107.7 प्रतिशत है। हम किसी जगह पर तीसरे नम्बर पर, किसी जगह पर पांचवें और किसी जगह पर सातवें नम्बर पर हैं। हमारी स्टेट में बाकी स्टेट्स के मुकाबले से क्राईम रेट घट रहा है। अध्यक्ष महोदय, बहादुरगढ़ में लड़कियों के साथ जो कुछ हुआ है यह बहुत दुख की बात है। ये 10 केस हैं और 10 में से 6 तो भजन लाल की सरकार के वक्त हुए थे और 4 हमारी सरकार के वक्त में हुए हैं। उनमें से एक केस ट्रेस हो गया है इसके अलावा कोई न कोई मुजरिम पकड़ा जाएगा तो सब कुछ पता चल जाएगा। अध्यक्ष महोदय, पलवल में दीवान जी और उन की पत्नी की हत्या हुई थी उनके मुजरिम पकड़े गए हैं। वे पकड़े तो किसी और केस में गए थे और पुलिस को भी नहीं पता था कि वे हत्या के केस में भी इन्वाल्व्ड हैं लेकिन उन मुजरिमों ने खुद ही उस हत्या के बारे में मान लिया था। वे मुजरिम गिरफ्तार हो चुके हैं। इस बारे में पता नहीं चौटाला साहब को पता है या नहीं पता है। अगर पता है तो वे जानबूझ कर कहते हैं। हमने जो वायदे किए थे वे सब के सब पूरे कर दिए हैं। एक वायदा जो बिजली के बारे में किया था वह भी हम दो साल में पूरा कर देंगे और 24 घंटे बिजली देंगे। इसे साथ ही गाबा साहब ने कहा कि पुलिस की नफरी कम है और वहां पर थाने बनने चाहिए। मैं इनकी बात से सहमत हूं और वहां पर नए थाने बना देंगे।

श्री धर्मबीर गाबा : अध्यक्ष महोदय, मेरी गुजारिश है कि फरीदाबाद और गुडगांव में आपकी अटैन्शन की आवश्यकता है। यू०पी० से क्रीमिनलस वहां पर आकर दहशत फैलाते हैं।

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, गाबा साहब ने जो भी बात कही है वह बिल्कुल सही कही है। कोई भी गलत बात नहीं कही है, कोई भी अनपार्लियामैंटरी बात नहीं कही है। मैं इनकी इस बात के लिए इनका धन्यवाद करता हूं। हमारे विरोधी पक्ष के मोलासा के एम०एल०ए० हैं उन्होंने भी ठीक बातें कहीं

[श्री बंसी लाल]

हैं। चौधरी धीरपाल जी भी ठीक बोले, यह तो इनका नेता है जो गलत बोलता है अब इसमें मैं क्या करूं। अध्यक्ष महोदय, गावा साहब ने पुलिस की नफरी वाली बात कही है मैं भी मानता हूं कि यह कम है। जितने जैड प्लस कैटेगरी की सुरक्षा के लोग हैं वह ज्यादातर गुड़गांव या फरीदाबाद में ही बैठे हैं और इसलिए हजारों कर्मचारी उन पर ही लगे हुए हैं। इसलिए अब मैं क्या करूं। अध्यक्ष महोदय, हम कोई भी बदले की भावना से काम नहीं करते और न ही हम किसी के साथ ज्यादती करते हैं। एक बात और विपक्ष के भाईयों ने कह दी कि बी०जे०पी० ने चुंगी खत्म करने का वायदा पहले किया था और वह अब तक पूरा नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, हमने इस बारे में एक कमेटी मिनिस्टर्ज की बनायी हुई है इस कमेटी की जो भी रिपोर्ट आएगी उसी के अनुसार हम कर देंगे। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने आपसे प्रार्थना की कि भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा विकास पार्टी के जितने भी वायदे हैं वह हम पांच सालों में पूरे करेंगे और किसी से भी पीछे नहीं हटेंगे।

श्री धर्मवीर गावा : अध्यक्ष महोदय, मेरी मुख्यमंत्री जी से एक और गुजारिश है कि पटीकुलर शहरों के अंदर जो सड़के हैं और जिनके बारे में मैंने कल भी आपको एक सजैशन दिया था कि या तो वे सारी म्यूनिसिपल कमेटी को दे दीजिए या पी०डब्ल्यू०डी० को दे दीजिए या हूडा को दे दीजिए या फिर मार्केटिंग बोर्ड को दे दीजिए ताकि कोई भी एक विभाग उनकी अच्छी तरह से मेंटीनेंस कर सके। अब किसी एक सड़क को म्यूनिसिपल कमेटी कहती है कि यह हमारी नहीं है और पी०डब्ल्यू०डी० कहता है कि यह हमारी नहीं है और मार्केटिंग बोर्ड कहता है कि हमारी नहीं है।

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो म्यूनिसिपल कमेटी की लिमिट के अंदर जितनी भी सड़के हैं उनकी मेंटीनेंस की जिम्मेदारी उन्हीं की है। हमने तो चुंगी भी नहीं बढ़ायी है जो 1952 से पहले चुंगी थी वही आज भी है। साथ ही हम हाउस टैक्स भी वसूल नहीं करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मुझे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन कहना पड़ रहा है कि म्यूनिसिपल कमेटी वाले भी पूरी चुंगी वसूल नहीं करते हैं जो आती है उसमें भी गड़बड़ होती है लेकिन इसके बावजूद भी हम मार्केटिंग बोर्ड की तरफ से और पी०डब्ल्यू०डी० की तरफ से शहरों की सड़कें ठीक करते ही जा रहे हैं। यह बात ठीक है कि शहरों की सड़कें खराब हैं और देहात में भी खराब हैं लेकिन मैं क्या करूं। मैं 25 साल पहले जिनको बनाकर गया था उसको इन्होंने ठीक भी नहीं किया तो अब मैं क्या करूं। परन्तु मैं तो फिर भी इनको ठीक करने में लगा हुआ हूं। चौटाला साहब ने एक बात अधिकारियों की सैर करने के बारे में कही तो अध्यक्ष महोदय, अधिकारी वहां काम से गए थे। लेकिन श्री ओमप्रकाश चौटाला जो कि लीडर ऑफ दि अपोजीशन हैं, के भाई जो उस समय एक्सपोर्ट कारपोरेशन के चेयरमैन थे 25 देशों की यात्राएं की थीं और 87 लाख 85 हजार रुपये इस कारपोरेशन का खर्च कर दिया था। वे एक बार यू०एस०ए० में किसी फेयर में चालीस दिन तक वहां रहे थे और अध्यक्ष महोदय, वह फेयर कौन सा था वह फेयर था कैटल का। जबकि अब ये हमें कहते हैं कि हमने आफिसर सैर करने के लिए भेज दिये। जबकि अध्यक्ष महोदय, वह फेयर केवल 14 दिन का ही होता है न कि चालीस दिन का । अध्यक्ष महोदय, कम्पट्रोलर और आडिटर जनरल की रिपोर्ट में भी इस बारे में पैरा बना हुआ है और अभी तक भी यह केस पैंडिंग है। इनके जो यह भाई बाहर गए। कीनिया में किसी सौदे पर दस्तखत कर आए उसमें पौने सात लाख रुपये का नुक्सान हुआ और हमें कह रहे हैं कि अफसरों को भेज दिया। अध्यक्ष महोदय, अफसर सरकारी काम से गए थे, बेकार कोई नहीं गया। सरकारी काम से डिसकशन करने के लिए गए थे और मलेरिया के इपीडेमिक के बारे में भी यूनीसेफ से बात कर आए और हमने मेवात में छिड़काव के लिए दवाई मंगवाई

और 14 करोड़ रुपये की दवाई का छिड़काव कराया है। मेवात में 4 छिड़काव कराए हैं और पूरी स्टेट में 3 छिड़काव कराए हैं। देवगौड़ा जी जब भारत सरकार में प्रधानमंत्री थे तो मेवात आए और 11 करोड़ रुपये मेवात के लिए स्पेशल मंजूर करके गए थे। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमें उसमें से आज तक एक पैसा भी नहीं मिला। हमारे पास पहले जो 12-14 फौगिंग मशीनें थीं उनमें से केवल 2 काम करती थीं। हमने 160 मशीनें हवाई जहाज से जर्मनी से मंगाई और दस माउंटिंग मशीनें मंगाई और 14 करोड़ की दवाई छिड़क चुके हैं।

अध्यक्ष महोदय, बस परमिटों के बारे में मैंने बता ही दिया है इसी प्रकार से प्रोहिबिशन के बारे में भी बता दिया कि बिल्कुल कामयाबी से चल रहा है। मानेसर की बात चौधरी भजन लाल ने भी की और गाबा जी ने भी की। वह प्रौजैक्ट डैड हो चुका था हमने उसे रिवाइज किया और चालू किया उस पर काम चल रहा है और विकास का काम जून-जुलाई में शुरू होगा। राम पाल माजरा ने कह दिया कि बैंक 8 एकड़ जमीन गिरवी रख लेता है। अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं है 8 एकड़ जमीन से किसान क्वालिफाई करता है और जमीन की कीमत को देखते हुए 2-3 या 4 एकड़ जमीन रखनी पड़ती है जितनी जरूरत होती है उतनी ही रखते हैं उससे ज्यादा नहीं रखते हैं, चौधरी भजन लाल ने कह दिया कि हरियाणा से इंडस्ट्रीज उठ-उठ कर चली गई। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा विकास पार्टी और बी०जे०पी० की सरकार आने के बाद एक भी इंडस्ट्री यहां से नहीं गई बल्कि हमने 106 मिडल यूनिटों को लाईसैंस दिए हैं और 7886 स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को लाईसैंस दिए हैं इस प्रकार इंडस्ट्रीज आई हैं, गई एक भी नहीं है।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : यदि हाउस की सहमती हो तो बैठक का समय 15 मिनट के लिए बढ़ा दिया जाए।

आवाजें : जी हां।

श्री अध्यक्ष : ठीक है। बैठक का समय 15 मिनट के लिए बढ़ाया जाता है।

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री धर्मबीर गाबा : अध्यक्ष महोदय, मेरा मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि सी०एल०यू० लैंड यूज का रेट कम कीजिए, इससे इंडस्ट्रीज को बड़ा नुक्सान हो रहा है।

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, चौटाला साहब बिस्कुटों के बारे कह रहे थे उसका जवाब बहन कमला वर्मा ने दिया था। एस०वाई०एल० कैनाल हम ही बनाएंगे और किसी के बस का सौदा नहीं है और गंगा नदी के प्रौजैक्ट का भी सर्वे हो रहा है। शारदा नदी जो गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूट्री है उसमें पानी बहुत है और उससे हरियाणा, राजस्थान और गुजरात को पानी मिलेगा। (थर्म्पिंग) 30 हजार क्यूसिक पानी की नहर बनाई जा रही है। अध्यक्ष महोदय, एक साथी ने जिक्र किया कि चौटाला साहब की मोटर छीन ली। अध्यक्ष महोदय, किसी महीने में उनकी गाड़ी का 30 हजार, 35 हजार रुपये से नीचे पैट्रोल खर्च नहीं हुआ । अक्तूबर-97 में उनकी एक गाड़ी का पैट्रोल का खर्च 51 हजार 468 रुपये है जबकि मेरी पांच गाड़ियों का पैट्रोल का खर्च 30 हजार 441 रुपये है। वह कार पानी पीती थी या क्या खाती थी मुझे पता नहीं। रणदीप सिंह सुर्जेवाला जी ने एक बात कही कि हरियाणा तो इन्टरनेट पर लाया

[श्री बंसी लाल]
जाये। उन्हें यह पता नहीं कि हरियाणा इन्टरनेट पर पहले से ही है। गाबा साहब का भी जवाब आ गया। हुड्डा की सड़कों का काम हुड्डा वाले ही कर रहे हैं और जब तक हुड्डा सड़कों का काम किसी संस्था को हैंड ओवर नहीं करती तब तक हुड्डा ही करती रहेगी। इसके बारे में किसी भी काम के लिए हुड्डा वाले ही प्लान पास करते हैं और उस सड़क का काम हुड्डा वाले ही करते हैं तथा म्यूनिसिपिलिटी की सड़कों का काम म्यूनिसिपिलिटी वाले ही करते हैं। जहां तक 1700 कर्मचारियों की छुट्टी करने का सवाल है यह छुट्टी हमने नहीं की है। यह तो सुप्रीमकोर्ट ने की है। हमने तो उन कर्मचारियों में से 450-475 के करीब जो इलीजिबल थे उनको नौकरी में वापस लिया है। अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि महामहिम राज्यपाल महोदय, का धन्यवाद प्रस्ताव पास किया जाये।

राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान

Mr. Speaker : Question is–

"That an Address be presented to the Governor in the following terms :-

> "That the Members of the Haryana Vidhan Sabha assembled in the Session are deeply grateful to the Governor for the Address which he has been pleased to deliver to the House on the 19th January, 1998."

The motion was carried.

वर्ष 1997-98 के अनुपूरक अनुमानों पर चर्चा तथा मतदान

(i) राज्य के राजस्वों पर प्रभारित व्यय के अनुमानों पर चर्चा

(ii) अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now discussion and voting on the Supplementary Estimates for the year 1997-98 will take place. As per the past practice, in order to save the time of the House, the demands on the order paper will be deemed to have been read and moved together. The Hon'ble Members can raise discussion on any demand but they are requested to indicate the demand number on which they wished to raise discussion.

> That a supplementary sum not exceeding Rs. 98,24,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1998 in respect of Demand No. 1-Vidhan Sabha.

> That a supplementary sum not exceeding Rs. 11,22,69,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1998 in respect of Demand No. 2-General Administration.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 50,03,21,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1998 in respect of Demand No. 3-Home

That a supplementary sum not exceeding Rs. 23,36,46,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1998 in respect of Demand No. 4-Revenue

That a supplementary sum not exceeding Rs. 3,54,55,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1998 in respect of Demand No. 5-Excise and Taxation

That a supplementary sum not exceeding Rs. 36,80,93,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1998 in respect of Demand No. 6.-Finance.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 14,14,05,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1998 in respect of Demand No. 8-Buildings and Roads.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 68,51,89,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1998 in respect of Demand No. 9-Education.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 35,76,22,000 for revenue expenditure and Rs. 41,37,82,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1998 in respect of Demand No. 10-Medical and Public Health.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 7,77,71,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1998 in respect of Demand No. 11-Urban Development.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 9,81,77,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1998 in respect of Demand No. 12-Labour and Employment.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 1,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1998 in respect of Demand No. 13-Social Welfare and Rehabilitation.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 3,26,19,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1998 in respect of Demand No. 14-Food and Supplies.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 4,35,42,00,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1998 in respect of Demand No. 15.-Irrigation

That a supplementary sum not exceeding Rs.10 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1998 in respect of Demand No. 16-Industries.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 4,32,34,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1998 in respect of Demand No. 18-Animal Husbandry.

That a supplementary sum not exceeding Rs.12,09,51,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1998 in respect of Demand No. 21-Community Development.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 8,32,23,000 for revenue expenditure and Rs. 10,55,00,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1998 in respect of Demand No. 23-Transport.

That a supplementary sum not exceeding Rs.70,98,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1998 in respect of Demand No. 24-Tourism.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 13,21,42,000 for Loans and Advances be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1998 in respect of Demand No. 25-Loans and Advances by State Government.

(No member rose to speak)

Mr. Speaker : Now the demands will be put to the vote of the House.

Mr. Speaker : Question is—

That a supplementary sum not exceeding Rs. 98,24,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1998 in respect of Demand No. 1-Vidhan Sabha.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 11,22,69,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1998 in respect of Demand No. 2-General Administration.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 50,03,21,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1998 in respect of Demand No. 3-Home

That a supplementary sum not exceeding Rs. 23,36,46,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1998 in respect of Demand No. 4-Revenue

That a supplementary sum not exceeding Rs. 3,54,55,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1998 in respect of Demand No. 5-Excise and Taxation

That a supplementary sum not exceeding Rs. 36,80,93,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1998 in respect of Demand No. 6.-Finance.

The Motion was carried

Mr. Speaker : Question is :–

That a supplementary sum not exceeding Rs. 14,14,05,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1998 in respect of Demand No. 8-Buildings and Roads.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 68,51,89,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1998 in respect of Demand No. 9-Education.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 35,76,22,000 for revenue expenditure and Rs. 41,37,82,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1998 in respect of Demand No. 10-Medical and Public Health.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 7,77,71,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1998 in respect of Demand No. 11-Urban Development.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 9,81,77,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1998 in respect of Demand No. 12-Labour and Employment.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 1,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1998 in respect of Demand No. 13-Social Welfare and Rehabilitation.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 3,26,19,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1998 in respect of Demand No. 14-Food and Supplies.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 4,35,42,00,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1998 in respect of Demand No. 15.-Irrigation

That a supplementary sum not exceeding Rs.10 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1998 in respect of Demand No. 16-Industries.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is-

That a supplementary sum not exceeding Rs. 4,32,34,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1998 in respect of Demand No. 18-Animal Husbandry.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is-

That a supplementary sum not exceeding Rs.12,09,51,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1998 in respect of Demand No. 21-Community Development.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is-

That a supplementary sum not exceeding Rs. 8,32,23,000 for revenue expenditure and Rs. 10,55,00,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1998 in respect of Demand No. 23-Transport.

That a supplementary sum not exceeding Rs.70,98,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1998 in respect of Demand No. 24-Tourism.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 13,21,42,000 for Loans and Advances be granted to the Governor to defray charges that will

come in the course of payment for the year ending 31st March, 1998 in respect of Demand No. 25-Loans and Advances by State Government.

The motion was carried.

अप्रैल से जुलाई, 1998 के लेखानुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान।

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now discussion and voting on Demands for Grants on account for April to July, 1998 will take place. Shri Randeep Singh Surjewala, Shri Ram Pal Majra, and Shri Virender Pal Ahlawat, M.L.As., have given notice of cut motions on Demand Nos. 2,3, 5 and 17. As any of the Hon'ble Members giving notice of cut motions is not present in the House the notices are not moved. As per the past practice and in order to save the time of the House, the demands on the order paper will be deemed to have been read and moved. Hon'ble Members can discuss any demand and are requested to indicate the demand number on which they wish to raise discussion.

That a sum not exceeding Rs. 2,88,36,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for a part of the year 1998-99 (from the 1st April to the 31st July, 1998) in respect of charges under Demand No. 1-Vidhan Sabha.

That a sum not exceeding Rs. 58,64,79,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for a part of the year 1998-99 (from the 1st April to the 31st July, 1998) in respect of charges under Demand No. 2-General Administration.

That a sum not exceeding Rs. 2,53,58,44,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for a part of the year 1998-99 (from the 1st April to the 31st July, 1998) in respect of charges under Demand No. 3-Home.

That a sum not exceeding Rs. 66,03,55,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for a part of the year 1998-99 (from the 1st April to the 31st July, 1998) in respect of charges under Demand No. 4-Revenue.

That a sum not exceeding Rs. 22,88,18,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for a part of the year 1998-99 (from the 1st April to the 31st July, 1998) in respect of charges under Demand No. 5-Excise & Taxation.

That a sum not exceeding Rs. 2,65,41,92,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for a part of the year 1998-99 (from the 1st April to the 31st July, 1998) in respect of charges under Demand No. 6-Finance.

That a sum not exceeding Rs. 4,32,97,58,000 for revenue expenditure and Rs. 4,67,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for a part of the year 1998-99 (from the 1st April to the 31st July, 1998) in respect of charges under Demand No. 7-Other Administrative Services.

That a sum not exceeding Rs.99,85,03,000 for revenue expenditure and Rs. 34,73,48,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for a part of the year 1998-99 (from the 1st April to the 31st July, 1998) in respect of charges under Demand No. 8-Buildings & Roads.

That a sum not exceeding Rs. 6,27,55,10,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for a part of the year 1998-99 (from the 1st April to the 31st July, 1998) in respect of charges under Demand No. 9-Education.

That a sum not exceeding Rs. 2,57,11,47,000 for revenue expenditure and Rs. 51,63,27,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for a part of the year 1998-99 (from the 1st April to the 31st July, 1998) in respect of charges under Demand No. 10-Medical & Public Health.

That a sum not exceeding Rs. 19,65,33,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for a part of the year 1998-99 (from the 1st April to the 31st July, 1998) in respect of charges under Demand No. 11-Urban Development.

That a sum not exceeding Rs. 29,21,79,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for a part of the year 1998-99 (from the 1st April to the 31st July, 1998) in respect of charges under Demand No. 12-Labour & Employment.

That a sum not exceeding Rs. 85,11,71,000 for revenue expenditure and Rs. 91,64,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for a part of the year 1998-99 (from the 1st April to the 31st July, 1998) in respect of charges under Demand No. 13-Social Welfare & Rehabilitation.

That a sum not exceeding Rs. 14,21,17,000 for revenue expenditure and Rs.3,96,84,47,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for a part of the year 1998-99 (from the 1st April to the 31st July, 1998) in respect of charges under Demand No. 14-Food & Supplies.

That a sum not exceeding Rs. 5,74,47,00,000 for revenue expenditure and Rs.1,35,00,00,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for a part of the year 1998-99 (from the 1st April to the 31st July, 1998) in respect of charges under Demand No. 15-Irrigation.

That a sum not exceeding Rs. 14,34,24,000 for revenue expenditure and Rs. 4,11,83,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for a part of the year 1998-99

(from the 1st April to the 31st July, 1998) in respect of charges under Demand No. 16-Industries.

That a sum not exceeding Rs. 98,09,34,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for a part of the year 1998-99 (from the 1st April to the 31st July, 1998) in respect of charges under Demand No. 17-Agriculture.

That a sum not exceeding Rs. 48,17,01,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for a part of the year 1998-99 (from the 1st April to the 31st July, 1998) in respect of charges under Demand No. 18-Animal Husbandry.

That a sum not exceeding Rs. 2,84,07,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for a part of the year 1998-99 (from the 1st April to the 31st July, 1998) in respect of charges under Demand No. 19-Fisheries.

That a sum not exceeding Rs. 22,29,61,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for a part of the year 1998-99 (from the 1st April to the 31st July, 1998) in respect of charges under Demand No. 20-Forest.

That a sum not exceeding Rs. 46,32,92,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for a part of the year 1998-99 (from the 1st April to the 31st July, 1998) in respect of charges under Demand No. 21-Community Development.

That a sum not exceeding Rs. 13,43,98,000 for revenue expenditure and Rs. 3,35,62,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for a part of the year 1998-99 (from the 1st April to the 31st July, 1998) in respect of charges under Demand No. 22-Co-operation.

That a sum not exceeding Rs. 2,11,30,66,000 for revenue expenditure and Rs. 18,95,67,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for a part of the year 1998-99 (from the 1st April to the 31st July, 1998) in respect of charges under Demand No. 23-Transport.

That a sum not exceeding Rs. 53,75,000 for revenue expenditure and Rs. 1,34,33,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for a part of the year 1998-99 (from the 1st April to the 31st July, 1998) in respect of charges under Demand No. 24-Tourism.

That a sum not exceeding Rs. 6,05,71,90,00 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for a part of the year 1998-99 (from the 1st April to the 31st July, 1998) in respect of charges under Demand No. 25-Loans and Advances by State Govt.

(No member rose to speak)

Mr. Speaker : Now the demands will be put to the vote of the House.

Mr. Speaker : Question is-

That a sum not exceeding Rs. 2,88,36,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for a part of the year 1998-99 (from the 1st April to the 31st July, 1998) in respect of charges under Demand No. 1-Vidhan Sabha.

That a sum not exceeding Rs. 58,64,79,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for a part of the year 1998-99 (from the 1st April to the 31st July, 1998) in respect of charges under Demand No. 2-General Administration.

That a sum not exceeding Rs. 2,53,58,44,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for a part of the year 1998-99 (from the 1st April to the 31st July, 1998) in respect of charges under Demand No. 3-Home.

That a sum not exceeding Rs. 66,03,55,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for a part of the year 1998-99 (from the 1st April to the 31st July, 1998) in respect of charges under Demand No. 4-Revenue.

That a sum not exceeding Rs. 22,88,18,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for a part of the year 1998-99 (from the 1st April to the 31st July, 1998) in respect of charges under Demand No. 5-Excise & Taxation.

That a sum not exceeding Rs. 2,65,41,92,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for a part of the year 1998-99 (from the 1st April to the 31st July, 1998) in respect of charges under Demand No. 6-Finance.

That a sum not exceeding Rs. 4,32,97,58,000 for revenue expenditure and Rs. 4,67,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for a part of the year 1998-99 (from the 1st April to the 31st July, 1998) in respect of charges under Demand No. 7-Other Administrative Services.

That a sum not exceeding Rs.99,85,03,000 for revenue expenditure and Rs. 34,73,48,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for a part of the year 1998-99 (from the 1st April to the 31st July, 1998) in respect of charges under Demand No. 8-Buildings & Roads.

That a sum not exceeding Rs. 6,27,55,10,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for a part of the year 1998-99 (from the 1st April to the 31st July, 1998) in respect of charges under Demand No. 9-Education.

That a sum not exceeding Rs. 2,57,11,47,000 for revenue expenditure and Rs. 51,63,27,000 for capital expenditure be granted to the Governor

to defray charges that will come in the course of payment for a part of the year 1998-99 (from the 1st April to the 31st July, 1998) in respect of charges under Demand No. 10-Medical & Public Health.

That a sum not exceeding Rs. 19,65,33,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for a part of the year 1998-99 (from the 1st April to the 31st July, 1998) in respect of charges under Demand No. 11-Urban Development.

That a sum not exceeding Rs. 29,21,79,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for a part of the year 1998-99 (from the 1st April to the 31st July, 1998) in respect of charges under Demand No. 12-Labour & Employment.

That a sum not exceeding Rs. 85,11,71,000 for revenue expenditure and Rs. 91,64,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for a part of the year 1998-99 (from the 1st April to the 31st July, 1998) in respect of charges under Demand No. 13-Social Welfare & Rehabilitation.

That a sum not exceeding Rs. 14,21,17,000 for revenue expenditure and Rs. 3,96,84,47,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for a part of the year 1998-99 (from the 1st April to the 31st July, 1998) in respect of charges under Demand No. 14-Food & Supplies.

That a sum not exceeding Rs. 5,74,47,00,000 for revenue expenditure and Rs. 1,35,00,00,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for a part of the year 1998-99 (from the 1st April to the 31st July, 1998) in respect of charges under Demand No. 15-Irrigation.

That a sum not exceeding Rs. 14,34,24,000 for revenue expenditure and Rs. 4,11,83,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for a part of the year 1998-99 (from the 1st April to the 31st July, 1998) in respect of charges under Demand No. 16-Industries.

That a sum not exceeding Rs. 98,09,34,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for a part of the year 1998-99 (from the 1st April to the 31st July, 1998) in respect of charges under Demand No. 17-Agriculture.

That a sum not exceeding Rs. 48,17,01,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for a part of the year 1998-99 (from the 1st April to the 31st July, 1998) in respect of charges under Demand No. 18-Animal Husbandry.

That a sum not exceeding Rs. 2,84,07,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for a part of the year 1998-99 (from the 1st April to the 31st July, 1998) in respect of charges under Demand No. 19-Fisheries.

That a sum not exceeding Rs. 22,29,61,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for a part of the year 1998-99 (from the 1st April to the 31st July, 1998) in respect of charges under Demand No. 20-Forest.

That a sum not exceeding Rs. 46,32,92,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for a part of the year 1998-99 (from the 1st April to the 31st July, 1998) in respect of charges under Demand No. 21-Community Development.

That a sum not exceeding Rs. 13,43,98,000 for revenue expenditure and Rs. 3,35,62,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for a part of the year 1998-99 (from the 1st April to the 31st July, 1998) in respect of charges under Demand No. 22-Co-operation.

That a sum not exceeding Rs. 2,11,30,66,000 for revenue expenditure and Rs. 18,95,67,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for a part of the year 1998-99 (from the 1st April to the 31st July, 1998) in respect of charges under Demand No. 23-Transport.

That a sum not exceeding Rs. 53,75,000 for revenue expenditure and Rs. 1,34,33,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for a part of the year 1998-99 (from the 1st April to the 31st July, 1998) in respect of charges under Demand No. 24-Tourism.

That a sum not exceeding Rs. 6,05,71,90,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the couse of payment for a part of the year 1998-99 (from the 1st April to the 31st July, 1998) in respect of charges under Demand No. 25-Loans and Advances by State Govt.

The motion was carried.

समितियों की रिपोर्टस पेश करना

(i) पब्लिक अकाउंटस कमेटी की 45वीं रिपोर्ट

Mr. Speaker : Now, Shri Anil Vij, Chairman, Committee on Public Accounts will present the Forty Fifth Report of the Committee on Public Accounts for the year 1997-98, on the Appropriation Accounts/Finance Accounts of the Haryana Government for the year 1993-94.

Chairman, Committee on Public Accounts (Shri Anil Vij) : Sir, I beg to present the Forty Fifth Report of the Committee on Public Accounts for the year 1997-98, on the Appropriation Accounts/Finance Accounts of the Haryana Government for the year 1993-94.

(ii) सबोर्डिनेट लैजिसूलेशन कमेटी की 29वीं रिपोर्ट

Mr. Speaker : Now, Shri Bijender Singh Kadian, Chairman, Committee on Subordinate Legislation will present the Twenty Ninth Report of the Committee on Subordinate Legislation for the year 1997-98.

Chairman, Committee on Subordinate Legislation (Shri Bijender Singh Kadian) : Sir, I beg to present the Twenty Ninth Report of the Committee on Subordinate Legislation for the year 1997-98.

बिल्ज़

(i) दि हरियाणा नौन-बायोडिग्रेडेबल गारबेज (कन्ट्रोल) बिल, 1988

Mr. Speaker : Now, the Local Government Minister will introduce the Haryana Non-Biodegradable Garbage (Control), Bill 1998 and also move the motion for its consideration.

स्थानीय शासन मंत्री (डॉ० कमला वर्मा) : अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (नियंत्रण) विधेयक, 1998 को प्रस्तुत करती हूं और यह भी प्रस्ताव करती हूं कि इस विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

Mr. Speaker : Motion moved-

That the Haryana Non-Biodegradable Garbage (Control) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is-

That the Haryana Non-Biodegradable Garbage (Control) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

SUB-CLAUSES (2 & 3) OF CLAUSE 1

Mr. Speaker : Question is-

That Sub-Clause (2&3) of Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 2

Mr. Speaker : Question is-

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 3

Mr. Speaker : Question is-

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 4

Mr. Speaker : Question is-

That Clause 4 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 5

Mr. Speaker : Question is-

That Clause 5 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 6

Mr. Speaker : Question is-

That Clause 6 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 7

Mr. Speaker : Question is-

That Clause 7 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 8

Mr. Speaker : Question is-

That Clause 8 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 9

Mr. Speaker : Question is-

That Clause 9 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 10

Mr. Speaker : Question is-

That Clause 10 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 11

Mr. Speaker : Question is-

That Clause 11 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 12

Mr. Speaker : Question is-

That Clause 12 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 13

Mr. Speaker : Question is-

That Clause 13 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 14

Mr. Speaker : Question is-

That Clause 14 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 15

Mr. Speaker : Question is-

That Clause 15 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 16

Mr. Speaker : Question is-

That Clause 16 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 17

Mr. Speaker : Question is-

That Clause 17 stand part of the Bill.

The motion was carried.

बैठक का समय बढ़ाना

Mr. Speaker : Is it the sense of the House that the time of the sitting be extended by 15 minutes ?

Voices : Yes.

Mr. Speaker : The time of the sitting is extended by 15 minutes.

CLAUSE 18

Mr. Speaker : Question is-

That Clause 18 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Schedule

Mr. Speaker : Question is-

That Schedule be the Schedule of the Bill.

The motion was carried.

Sub Clause (1) of Clause 1

Mr. Speaker : Question is-

That Sub-Clause (1) of Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the Local Govt. Minister will move that the Bill be passed.

Local Government Minister (Dr. Kamla Verma) : Sir, I beg to move-

That the Bill be passed.

(i) दि हरियाणा नौन-बायोडिग्रेडेबल गारबेज (कन्ट्रोल) बिल, 1998 (पुनरारम्भ)

Mr. Speaker : Motion moved-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(ii) दि हरियाणा एफिलिएटिड कालेजिज़ (सिक्योरिटी ऑफ सर्विस) अमैंडमैंट बिल, 1998

Mr. Speaker : Now the Education Minister will introduce the Haryana Affiliated Colleges (Security of Service) Amendment Bill, 1998, and will also move the motion for its consideration.

Education Minister (Shri Ram Bilas Sharma) : Sir, I beg to introduce the Haryana Affiliated Colleges (Security of Service) Amendment Bill, 1998.

Sir, I also beg to move-

That the Haryana Affiliated Colleges (Security of Service) Amendment Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved-

That the Haryana Affiliated Colleges (Security of Service) Amendment Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is-

That the Haryana Affiliated Colleges (Security of Service) Amendment Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

CLAUSE 2

Mr. Speaker : Question is-

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 1

Mr. Speaker : Question is-

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the Education Minister will move that the Bill be passed.

Education Minister (Shri Ram Bilas Sharma) : Sir, I beg to move-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is

That the Bill be passed.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the House is adjourned till 3.00 P.M. today.

*14.00 hours (The Sabha then *adjourned till 3.00 P.M. today, the 22nd January, 1998).

30005—H.V.S.—H.G.P. Chd.